वर्ष : 1 अंक : 4 जून, 2026 मूल्य : ₹25

RNI : UPHIN/26/A0322

पंचायत वॉयस

पंचायत से परिवर्तन...

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

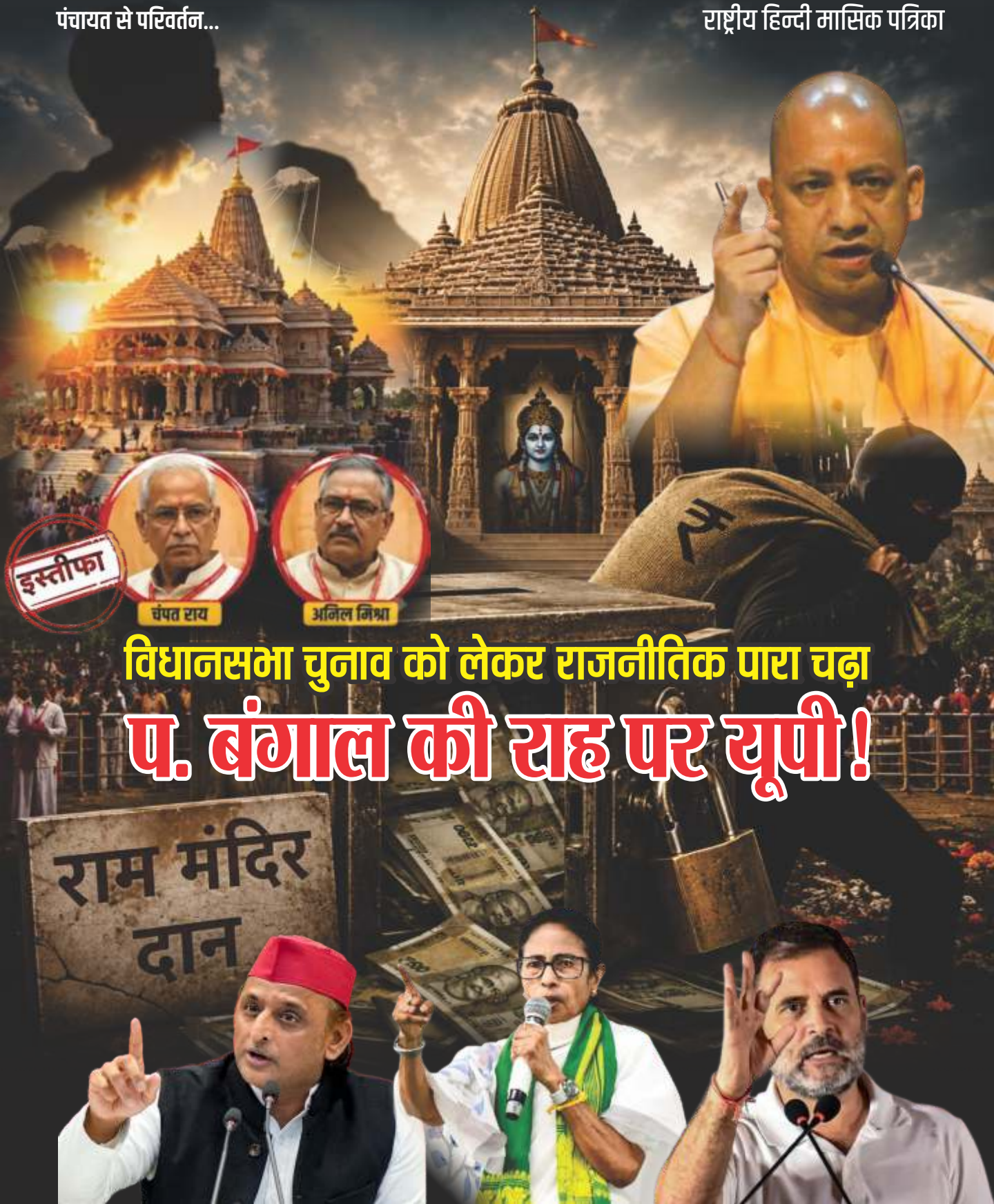

विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा

प. बंगाल की राह पर यूपी!

सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस

सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी

निर्माणाधीन कॉलेज

संचालित द्वारा- पं0 मनबोध चौबे एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट

भारत सरकार और यू0जी0सी0 अप्रूव्ड युनिवर्सिटी से डिग्री/डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स (B.VOC) करें।

डिप्लोमा 1 साल | **एडवांस डिप्लोमा** 2 साल | **डिग्री** 3 साल

- लैब टेक्नीशियन
- ओ.टी. टेक्नीशियन
- आप्टोमेट्री टेक्नीशियन
- डायलिसिस टेक्नीशियन
- रेडियोलॉजी एण्ड मेडिकल इजेजिंग
- कार्डिक केयर टेक्नीशियन
- हॉस्पिटल स्ट्रेलाइजेशन
- पेशेंट केयर मैनेजमेंट
- हॉस्पिटल मैनेजमेंट
- डायटिक्स एण्ड न्यूट्रीशन
- बी.पी.टी.- बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी
- एनेस्थिसीया
- फार्मेसी असीस्टेंट
- अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड एजुकेशन
- रुरल हेल्थ एण्ड सैनीटेशन
- बी-फार्मा*/डी-फार्मा*

प्रवेश प्रारम्भ, 2026-27

SC/ST/OBC
छात्रों के लिए स्कालरशीप
40% तक की छूट

आलोक पांडेय मिंटू
प्रबंधक

9336548360, 9120008360

पता- ग्रा0 कुलडोमरी (मेडरदह) निकट- अनपरा-ओबरा रोड, जिला-सोनभद्र
प्रशासनिक ब्लाक- डिबुलगंज (अनपरा) वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग-सोनभद्र
ब्रांच- सांईनाथ हॉलिस्टिक हॉस्पिटल, हिंदुआरी, राबर्ट्सगंज- सोनभद्र

डिप्लोमा/ डिग्री कोर्सेस सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी हेतु मान्य

Email- sardarvpatelcollegepharmacy@gmail.com ★ https://svbpcsonbhadra.org/

आलोक पांडेय मिंटू - प्रबंधक, अनपरा सोनभद्र, मो. 7398064538

इस अंक में

पंचायत से परिवर्तन
पंचायत वॉयस
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
वर्ष 01 अंक 03 मई-2026

सलाहकार संपादक
रामेंद्र सिन्हा
रविकांत प्रसाद

संपादक
राजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रबंधक
नीलम श्रीवास्तव

विज्ञापन प्रबंधक
आदर्श श्रीवास्तव

राज्य ब्यूरो
बिहार : प्रभात कुमार
झारखंड : कौस्तुभ कुमार मलयज
जम्मू-कश्मीर : राज लक्ष्मी

ब्यूरों
गोरखपुर : निखिल पाण्डेय
गोरखपुर : सौम्या द्विवेदी
देवरिया : गणेश धर द्विवेदी
सुल्तानपुर : नम्रता श्रीवास्तव
मिर्जापुर : संतोष शंकर

ग्राफिक्स - कुमार सर्वेश

प्रधान कार्यालय
24/112, दुर्गा मंदिर के पीछे, राघव नगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001

स्वामी, प्रकाशक राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा 39, खसरा नं.–166, नियर यूनिटी सिटी, कल्याणपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226022 से प्रकाशित, संपादक राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा मुद्रक नीलम श्रीवास्तव द्वारा नीलम प्रिंटिंग प्रेस, 41/381, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001 से मुद्रित।

संपादक
राजेश कुमार श्रीवास्तव
संपर्क नं. : 9876917688

संपादकीय कार्यालय
नियर यूनिटी सिटी, गोल चौराहा, कल्याणपुर, लखनऊ–226022

panchayatvoice.up@gmail.com

www.panchayatvoice.in

समाचारों का चयन PRP ACT 2023 के अनुसार किया गया है।
सभी विवाद लखनऊ न्यायालय के अंतर्गत मान्य होंगे।

सभी पद अवैतनिक हैं

RNI : UPHIN/26/A0322

10

विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा

प. बंगाल की राह पर यूपी !

03

RSS का अब बदलेगा स्ट्रक्चर

ब्लू प्रिंट तैयार, मार्च 2027 से प्रभावी होगी नई संरचना

04

गांव की सरकार "प्रधान जी" असली चाबी कलेक्टर साहब के हाथ

06

अलीगंज अग्निकांड की घटना का जिक्र होते ही कलेजा कांप उठता है

संपादकीय

संपादक की कलम से

संपादकीय

यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा

देवालय से न्यायालय तक घिरती जा रही भाजपा सरकार

उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। समय से पहले चुनाव कराए जाने की अनौपचारिक खबरें भी हैं। यह मानकर सभी दल अपनी-अपनी तैयारी में जुट गए हैं, यानी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। हाल ही में संपन्न हुए देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आए परिणाम और बंगाल फतह के बाद राजनीति की सुपर पॉवर भाजपा की नजर अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर है। यहां 2017 से चली आ रही भाजपा सरकार का दबदबा कायम रहे, इसको लेकर सुपर पॉवर भाजपा के रणनीतिकार जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने और इन वर्षों में भारत के अभूतपूर्व परिवर्तन को आधार बनाकर नित्य नए प्रयोग सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन दिनों राज्य में तूफानी दौरा तेज है। मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश को वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर, वर्ष 2036 तक 2 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य और विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प दोहरा रहे हैं। दनादन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सरकार की प्रतिबद्धता और विकास मॉडल को रेखांकित कर विपक्ष को घेर रहे हैं, लेकिन इसी बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण ने कमजोर पड़े विपक्ष को ताकतवर बना दिया। इसके पहले तेल-गैस संकट के बीच बढ़ती महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विपक्ष मुखर रहा।

भाजपा की राजनीति का आधार स्तंभ रहा राम मंदिर के दानपात्र (चढ़ावे) से करोड़ों रुपये की चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के विवाद से भाजपा इस कदर घिरी कि उसे सबसे ज्यादा रक्षात्मक होना पड़ा। विपक्षी दलों के लिए चढ़ावा चोरी, अयोध्या में जमीन खरीद विवाद का मामला सत्ता पक्ष को घेरने का एक बड़ा हथियार बन गया। विपक्ष इस मुद्दे को "भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात" और "भगवान के घर में लूट" के रूप में प्रचारित कर रहा है, जिससे भाजपा की 'ईमानदार और धार्मिक' छवि धूमिल हो रही है। न्यास के शीर्ष पदाधिकारियों जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा पर इस विवाद की आंच और फिर त्यागपत्र यह दर्शाता है कि विवाद की छाप गहरी है।

अब सवाल यह उठता है कि हिंदुत्व के ब्रांड एंबेसडर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि तले भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत की आशा लगाए बैठा है, उसका क्या होगा...?, सवाल यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी टूटेगी...?, जिस तरीके से योगी कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को सीधे चुनौती दी और कहा कि "अगर हिम्मत है तो अपनी पार्टी को टूटने से बचाकर दिखाएं"। इसके बाद जो नई बहस छिड़ी, इसे क्या समझा जाए...?

वैसे, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के हाथ तेल-गैस संकट के बीच बढ़ती महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दे तो पहले ही थे, ताजा और मजबूत मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने दे दिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष पहले से सत्ता पक्ष को घेरता रहा है, लेकिन हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को गलत ठहरा दिया। कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष को और बल दे दिया। यानी देवालय से लेकर न्यायालय तक भाजपा सरकार घिरती जा रही है। ऐसे में यह तकरीर लाजमी है कि इतनी घेराबंदी का चक्रव्यूह भाजपा कैसे तोड़ेगी, यह सवाल गंभीर है!■

सादर।

संपादक

राजेश कुमार श्रीवास्तव

Panchayat Voice

RSS का अब बदलेगा स्ट्रक्चर

ब्लू प्रिंट तैयार, मार्च 2027 से प्रभावी होगी नई संरचना

राजेश श्रीवास्तव

देश में बदलते राजनैतिक हालात को भांपते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भी अपनी कार्य प्रणाली बदलने जा रहा है। देश के हर गांव, हर ग्राम पंचायत और हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच और पकड़ को मजबूत बनाने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि संघ 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, लेकिन जीरो डेप्थ पर संघ कार्य का पहुंचना अभी बाकी है। यहां तक अपनी पहुंच बनाने के उद्देश्य से संघ अपनी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है।

देश में अब नवीन संरचना के माध्यम से संघ अपने मकसद को अंजाम देगा। इसका ब्लू प्रिंट तैयार हो चुका है। मार्च 2027 में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। इस घोषणा के साथ ही संघ अपनी नई ऊर्जा के साथ कार्यक्षेत्र में उतरेगा ताकि व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री कही जाने वाली संघ की शाखा देश के हर गांव, हर ग्राम पंचायत तक पहुंच सके।

संघ सूत्रों के मुताबिक अभी तक पूरे भारत में संघ की संरचना के अनुसार संघ कार्य को 46 प्रान्तों में बांटा गया था किन्तु नई संरचना में इसकी संख्या अब 85 के करीब पहुंच जाएगी और इसे संभाग के नाम से जाना जाएगा। यानी करीब डेढ़गुना से अधिक फैलाव हो जाएगा। संघ ने नई संरचना का आधार शासकीय प्रदेश को माना है और इसी के अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश में कार्य की दृष्टि से कई-कई संभागों की संरचना की गई है। अब मुख्य रूप से आखिल भारतीय कार्यकारिणी होगी उसके नीचे क्षेत्र कार्यकारिणी तथा उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी होगी। तत्पश्चात संभाग कार्यकारिणी होगी। अब प्रांत संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक की जगह संभाग संघ चालक, कार्यवाह तथा प्रचारक का दायित्व होगा। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां संघ की दृष्टि से कुल 6 प्रांत थे और नई संरचना के तहत अब 10 संभाग कर दिए गए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश पहले दो क्षेत्रों में विभाजित था, लेकिन अब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक क्षेत्र की संरचना कर दी गई है।

नई संरचना के तहत अब जितने शासकीय प्रदेश हैं, उसी के आधार पर संघ ने भी प्रदेश प्रचारक और प्रदेश कार्यवाह कुछ कार्यकारिणी के सदस्य के साथ अपनी रचना को आकार दिया है। इस नई संरचना में प्रदेश संघचालक का दायित्व समाप्त कर दिया गया है। अभी तक पूरे भारत में संघ की दृष्टि से 46 प्रांत थे, लेकिन अब नई संरचना में 85 संभाग की रचना की गई है।

> - देश में बदलते राजनैतिक हालात को भांपते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भी बदल रहा अपनी कार्य संस्कृति
> - देश के हर गांव, हर ग्राम पंचायत और हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच और पकड़ बनाने की योजना

नई संरचना में कार्य क्षेत्रों में तो बदलाव किए ही गए हैं, अपितु उन बैठकों के स्वरूप में भी बदलाव किए गए हैं, जिनमें संघ कार्य को आकार दिया जाता है।

नई संरचना के मुताबिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक तीन वर्ष में एक बार होगी और यह बैठक अनिवार्य रूप से संघ मुख्यालय नागपुर में ही होगी। इसमें एक व्यवस्था के तहत दो वर्ष में क्षेत्र स्तर बैठकों को कराने की रचना भी बनाई गई है।

उम्मीद है कि जनवरी 2027 में इंदौर में होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ अपनी नई संरचना के आकार पर अंतिम मुहर लगा देगा। इसके बाद नए दायित्वधारी ही मार्च 2027 में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में भाग लेंगे और इसी के साथ संघ की नई संरचना अस्तित्व में आ जाएगी।

संघ की पहले की संरचना में प्रांत प्रचारक, प्रांत कार्यवाह (जेनरल सेक्रेटरी) और प्रांत संघचालक होते थे, अब ये प्रांत नहीं संभाग के दायित्व के नाते जाने जाएंगे। नीचे की सारी संरचनाएं पूर्व की भांति ही कार्य करेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे नगर/खंड, जिला, विभाग यहीं रहेंगे। अभी संघ कार्य खंड (ब्लॉक)/मंडल तक पहुंच बनाने की दृष्टि से कार्य कर रहा था, लेकिन नई संरचना के तहत ग्राम पंचायत स्तर तक संघ कार्य पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नई संरचना को लेकर मंथन बैठक हो चुकी है। जबलपुर में कार्यकारी मंडल और हरियाणा के समालखा में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। हाल ही में पुरानी संरचना के तहत सिद्धार्थनगर के तेतरी बाजार में गोरक्षप्रांत की प्रांत योजना की भी बैठक हो चुकी है। इस बैठक में भी संघ की नई संरचना और उसके तहत नए दायित्व और कार्य को लेकर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इस बैठक को अब पुरानी संरचना की अंतिम बैठक मानी गई और संभावना जताई गई कि अब अगली बैठक नई संरचना के तहत ही होगी।■

गांव की सरकार "प्रधान जी" असली चाबी कलेक्टर साहब के हाथ

नहीं चलेगी मनमर्जी, सरकारी फरमान से 'प्रधानजी' मायूस!

गणेश धर द्विवेदी

प्रदेश में ग्राम पंचायतों को लेकर योगी सरकार के फैसले ने निवर्तमान ग्राम प्रधान जी की धड़कन बढ़ा दी है। प्रधान जी प्रशासक तो बन गए, लेकिन अब असली चाभी यानी 'मास्टर की' कलेक्टर साहब के पास रहेगी। बगैर उनके परमिशन के प्रधान जी कोई नया काम नहीं कर पाएंगे।

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें ही प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रधान जी लोग बेहद खुश थे, किंतु नए फरमान ने ग्राम प्रधान जी लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। अब प्रधान जी की मनमर्ज़ी नहीं चलेगी, क्योंकि पंचायती राज विभाग ने कड़े और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के आते ही प्रधान जी लोगों का उत्साह चिंता में बदल गया है। नए शासनादेश के तहत प्रधान जी अपनी मर्जी से कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं कर पाएंगे और न ही पंचायत के फंड से नया पैसा खर्च कर

पंचायत चुनाव : योगी सरकार करेगी अपील

उधर, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद योगी सरकार ने उन्हें ही प्रशासक के रूप में नियुक्त कर उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी और अटकलों पर एक तरह ब्रेक लगा दिया था। इस चुनाव के दावेदार भी यह मान बैठे थे कि अब यह चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन हाल फिलहाल के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी रिपोर्ट के साथ टाइमलाइन मांगी है। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासक नियुक्त करना डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है जो अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस ओदश के बाद राज्य सरकार अपील करेगी। अब सबकी नजर 13 जुलाई पर टिकी है।

सकेंगे। अगर जरूरी है तो जिले के मुखिया यानि कलेक्टर साहब की हरी झंडी लेनी होगी।

नए फैसले ने ग्राम प्रधानों के अधिकारों पर लगाम लगा दी है। प्रशासक बने प्रधान उन्हीं पुराने और पहले से चल रहे विकास कार्यों का भुगतान कर सकेंगे जो पहले से स्वीकृत हैं। अगर गांव में कोई नई योजना शुरू करनी हो, किसी भी प्रकार की सरकारी खरीद करनी हो या फिर कोई नया निर्माण कार्य हाथ में लेना हो तो कलेक्टर साहब की लिखित अनुमति अनिवार्य है।

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था और 27 मई से निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। प्रधानों को लगा था कि पंचायतों का काम पहले की तरह ठाट-बाट से चलेगा, लेकिन पंचायती राज विभाग के नए आदेश ने खेल पलट दिया है। प्रशासक पहले से स्वीकृत, निर्माणाधीन या पूर्ण हो चुके कार्यों का भुगतान करा सकेंगे। नए काम के लिए प्रस्ताव तैयार कर डीपीआरओ के माध्यम से डीएम के पास भेजना होगा। डीएम की अनुमति के बाद ही काम शुरू होगा। अर्थात अब गांव में खड़ंजा, नाली, इंटरलॉकिंग, हैंडपंप या अन्य कोई नया काम प्रधान जी की मर्जी से नहीं, बल्कि कलेक्टर के आदेश से होगा। जरूरत पड़ी तो प्रस्तावित कार्यों की जांच भी होगी।

प्रशासक के पद पर रहते हुए प्रधान कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। यदि गांव में कोई विशेष या बेहद जरूरी मामला सामने आता है तो उसकी फाइल डीपीआरओ के जरिए डीएम को भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि आने वाले पंचायत चुनावों से पहले सरकारी फंड का दुरुपयोग न हो सके और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। सरकार के इस कड़े कदम से यह साफ हो गया है कि अब प्रशासक बने प्रधान जी बिना कलेक्टर साहब की अनुमति के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब गांव की सरकार की असली चाबी सीधे कलेक्टर साहब के हाथ में पहुंच गई है।

प्रधानों को उम्मीद थी कि प्रशासक बनने के बाद भी उनके जलवे और अधिकार पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन अब उन्हें छोटे से छोटे नए काम के लिए भी सरकारी दफ्तरों की चौखट पर चक्कर काटनी पड़ेंगी। कलेक्टर साहब की संस्तुति और जांच-परख के बाद ही गांवों में कोई भी नया कार्य शुरू कराया जा सकेगा।

उधर, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद योगी सरकार ने उन्हें ही प्रशासक के रूप में नियुक्त कर उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी और अटकलों पर एक तरह ब्रेक लगा दिया था। इस चुनाव के दावेदार भी यह मान बैठे थे कि अब यह चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन हाल फिलहाल के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी रिपोर्ट के साथ टाइमलाइन मांगी है। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासक नियुक्त करना डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है जो अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस ओदश के बाद राज्य सरकार अपील करेगी। अब सबकी नजर 13 जुलाई पर टिकी है।■

www.panchayatvoice.in

देवरिया में स्वच्छता अभियान अधूरा

सात हजार से अधिक परिवार आज भी खुले में शौच को विवश

बजट के अभाव में अटकी शौचालय योजना, शासन से धनराशि मिलने का इंतजार

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत देवरिया जिले को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए हजारों पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई, लेकिन बजट की कमी के कारण यह योजना अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकी है। नतीजतन जिले के 7,380 परिवार आज भी खुले में शौच करने को विवश हैं। देवरिया जनपद में कुल 1,121 ग्राम पंचायतें और लगभग 2,162 राजस्व गांव हैं। अभियान के तहत 1,63,870 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 97,434 लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी की गई, जबकि शौचालय निर्माण पूरा करने वाले 40,047 लाभार्थियों को दूसरी किस्त का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके बावजूद हजारों पात्र परिवार अब तक योजना के लाभ से वंचित हैं। जानकारी के अनुसार, योजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष लाभार्थियों को स्वीकृति नहीं मिल सकी। जिला पंचायत राज विभाग ने शासन को बजट की मांग भेजी है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी, पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त भेजी जाएगी। निर्माण कार्य पूरा होने और सत्यापन के बाद दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। शौचालय नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम और रात के समय खुले में शौच जाना सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छता अभियान का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब प्रत्येक पात्र परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि शासन से बजट मिलते ही शेष पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें शासन पर टिकी हैं कि लंबित बजट कब जारी होगा और जिले के हजारों परिवारों को खुले में शौच की विवशता से कब मुक्ति मिलेगी।■

"स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजना व्यक्तिगत शौचालय बनवाने की थी, इसके तहत पात्र व्यक्तियों को आनलाइन आवेदन करना था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किए। कुछ लोगों को पहली किस्त खाते में हस्तांतरित कर दी गई। वही कुछ पात्रों को दूसरी किस्त भी मिली। इसके अलावा काफी संख्या में पात्र लोगों को एक भी किस्त नसीब नहीं मिली और सत्र समाप्त हो गया। इसके कारण कई लोगों के शौचालय आज भी अधूरे पड़े हुए।"

- मनोहर यादव,
ग्राम प्रधान,
बनकट बहादुर,
पोखभिंडा, देवरिया

हादसा

हक़ीक़त परत दर परत

22 जून 2026 का दिन राजधानी लखनऊ के लिए काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ

अलीगंज अग्निकांड की घटना का जिक्र होते ही कलेजा कांप उठता है

15 विद्यार्थियों की मौत के साथ-साथ 15 परिवारों का सपना अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में जलकर भस्म हो गया

पंचायत वॉयस, लखनऊ

22 जून 2026, का दिन राजधानी लखनऊ के लिए काले अध्याय के रूप दर्ज हुआ। 20 से 22 साल के 15 विद्यार्थियों की मौत के साथ-साथ 15 परिवारों का सपना अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में जलकर भस्म हो गया। यदि सिस्टम जागरूक होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। सिस्टम जागा, लेकिन 15 विद्यार्थियों की मौत के बाद, लेकिन तब तक सबकुछ खत्म हो चुका था। अपने बच्चों के बढ़ते उम्र के साथ माता-पिता और पारिवारिकजन की आंखों में जो सपना आकार ले रहा था, वह साकार होने से पहले ही सिस्टम की खामियों के बारूद से बिखर गया। बारूद इसलिए कि जिस तीन मंजिला इमारत में कोचिंग सेंटर चल रहा था, वहां घर होना था, क्योंकि उस भूखंड पर एकल आवासीय भवन का नक्शा स्वीकृत था, लेकिन वहां तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया।

अब सवाल यह खड़ा होता है कि तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रातों-रात तो खड़ा नहीं हो गया...?, साफ है कि इसके पीछे बड़े खेल किए गए होंगे और इस खेल ने आवासीय भवन को तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते यह बारूदी इमारत बन

गई और धू-धू कर जल गई। इस अग्निकांड ने 15 परिवारों के सपनों को जला कर राख कर दिया।

राज्य सरकार ने 15 मौतों की खबर के बाद 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घेषणा कर दी, लेकिन सवाल यह है कि सहायता राशि उन परिवारों के सपने की भरपाई कर पाएगी, जो सपना अपनी बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ पारिवारिकजन देख रहे थे। कितने परिवारों के तो घर के चिराग बुझ गए।

सवाल सख्त है, लेकिन मौत के सौदागर धंधेबाजों को सबक सिखाने के लिए राज्य सरकार को कठोर कानून बनाकर उन सभी के ऊपर जो भी इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करें। यहीं नहीं इस अग्निकांड के प्रभावित सभी परिवारों के आजीवन भरण-पोषण के लिए उनकी कमाई गई अवैध अकूत संपत्तियों को जब्त कर के प्रभावित सभी परिवारों को सौंप दें, तब शायद मौत के सौदागर धंधेबाजों को सबक मिले, ताकि जिंदगियां अकाल मौत के मुंह में जाएं।

22 जून को राजधानी लखनऊ में अलीगंज के पुरनिया इलाके में अग्निकांड की घटना का जिक्र होते ही कलेजा कांप उठता है। धू-धू कर जल रही तीन मंजिला इमारत में धूंए की गुबार के बीच खिड़कियों के पास मदद की आस करते लोग, नीचे जमा भीड़, दमकल की गाड़ियां और राहत-बचाव अभियान के कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 15 मौतों के बाद जो सवाल खड़े हुए उन सवालों ने सिस्टम के पोल खोल दिए।

नई दिल्ली के मालवीय नगर में तीन जून को 5 मंजिला होटल में लगी भीषण आग में 23 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में मरने वाले अधिकांश नागरिक विदेशी थे। इस भयावह घटना के बावजूद हमारे अधिकारी जगे नहीं और सुधार करने की कोशिश नहीं की, जिसका परिणाम 19 दिन बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के

पुरनिया इलाके की दर्दनाक घटना में मरने वाले बच्चों के अलावा अपनी जान बचाने के लिए कई छात्रों ने ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे वे गंभीर रुप से घायल हो गए।

वैसे, उत्तर प्रदेश में हुए बड़े अग्निकांडों में कानपुर के चमनगंज में जूता फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में पांच लोगों की मौत हो गई। गल्लामंडी में लगी आग से सैकड़ों दुकानें और वाहन जल गए। पुराने कानपुर में आग लगने से व्यापारियों की जान चली गई। आगरा की 14 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। लखनऊ के विकास नगर में दो सौ से अधिक झुग्गियां जल गईं। लखनऊ के लेवाना होटल की त्रासदी अभी भी लोगों के जेहन में ताजा है। हर घटना के बाद जांच हुई, कायदे-कानून की रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन लागू नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो एक जैसी घटनाएं बार-बार सामने नहीं आतीं।

लखनऊ में अलीगंज की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर उत्तर प्रदेश आग की घटनाओं से सबक क्यों नहीं ले रहा है? क्यों हर बार चेतावनी को नजर अंदाज किया जाता है...? क्यों हर अग्निकांड के बाद वही खामियां फिर सामने आती हैं...? और आखिर क्यों लोगों की जान जाने के बाद ही व्यवस्था की नींद टूटती है...?...अलीगंज के जिस तीन मंजिला इमारत में आग लगी उसके अवैध निर्माण की कहानी तेजी से फैल चुकी है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिस भूखंड पर एकल आवासीय भवन का नक्शा स्वीकृत कराया गया था, वहां तीन मंजिला व्यावसायिक परिसर खड़ा हो गया। गेमिंग सेंटर संचालित होने लगा। बड़ी संख्या में लोग वहां आने-जाने लगे, लेकिन भवन की मूल स्वीकृति और वास्तविक उपयोग के बीच का अंतर किसी को दिखाई नहीं दिया या फिर देखने के बावजूद अनदेखा किया गया।

अग्निकांड के बाद हरकत में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भवन में सेटबैक मानकों का पालन नहीं किया गया था। कवरेज एरिया निर्धारित सीमा से कहीं अधिक था। बेसमेंट का निर्माण नियमों के विपरीत था। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भवन की ऊंचाई भी तय सीमा से अधिक बताई जा रही है। एलडीए के रिकॉर्ड में कई आवश्यक स्वीकृतियों और एनओसी का स्पष्ट विवरण भी उपलब्ध नहीं है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ...? यह निर्माण रातों-रात तो नहीं हुआ होगा। महीनों तक निर्माण कार्य चला होगा। इंजीनियरों, अवर अभियंताओं, जोनल अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में पूरा इलाका आता होगा। फिर भी

हादसा

यदि एक आवासीय भवन व्यावसायिक परिसर में बदल गया तो इसका अर्थ केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी राज्य में विद्युत सुरक्षा मानकों को लागू करना है। बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, अस्पतालों, मल्टीप्लेक्स और अन्य भवनों की सुरक्षा जांच कर एनओसी जारी करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसी विभाग के पास है। करीब तीन वर्ष पहले राजधानी में व्यापक सर्वे कराया गया था। सर्वे पूरा होने के बाद पिछले वर्ष लगभग 1070 प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं थीं। इनमें से 324 प्रतिष्ठानों में गंभीर खामियां थीं। अस्पतालों, नर्सिंग होम, व्यावसायिक भवनों और अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। उन्हें कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ...? इस अहम सवाल का जवाब अलीगंज अग्निकांड ढूढ़ रहा है।

जानकारों की मानें तो यदि नोटिसों का पालन सुनिश्चित कराया गया होता, समय-समय पर दोबारा निरीक्षण किए गए होते, नियमों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई हुई होती, तो संभव है कि अनेक भवनों में सुरक्षा मानक सुधर गए होते।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के जारी एक बयान के मुताबिक सर्वे के बाद प्रतिष्ठानों को व्यवस्था सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब नए सिरे से पड़ताल कराई जाने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यह कि जब खतरे पहले से दर्ज थे, तो नए सिरे से पड़ताल की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है...?■

अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाअभियान शुरू कर दिया गया। इसके तहत पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग सहित तमाम सरकारी विभागों की टीमों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और नियमों की अनदेखी पर उन्हें सील किया। इसी के तहत कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई के प्रतिष्ठान को भी नियमों का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में शहरों में कोचिंग संस्थानों व अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों व प्रतिष्ठानों को सील किया गया। इनमें आकाश, एलन समेत कई बड़े कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले में अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करें। प्रदेश के 72 जिलों में पंजीकृत 3172 कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार संस्थानों का व्यापक सर्वे कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जो संस्थान उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। निरीक्षण में भवन व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच शामिल होगी। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुरक्षित शैक्षिक वातावरण देना शासन की प्राथमिकता है। हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित वातावरण मिले और कोचिंग संस्थानों में निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो, विभाग इसके लिए काम करेगा। इस संबंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा निधि श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।■

सूचना

लखनऊ के इन इलाकों में न खरीदें जमीन, डीडीए ने लगायी रोक

आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी योजना होगी विकसित

पंचायत वॉयस, लखनऊ

यदि आप लखनऊ के कुछ खास इलाकों में जमीन खरीदना चाहते हैं, तो पहले उसकी सही जानकारी ले लीजिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी योजना के प्रथम चरण में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। एलडीए ने इस सम्बंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सम्बंधित क्षेत्रों में भूमि अर्जन प्रक्रिया वर्ष-2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम की धारा-11 लागू कर दी है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित क्षेत्र में बिना जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का भूमि हस्तांतरण, विक्रय अथवा क्रय नहीं किया जा सकेगा। साथ ही प्रभावित भू-स्वामियों एवं स्थानीय निवासियों को अपनी आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियों का निस्तारण जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई के उपरांत किया जाएगा।

उपाध्यक्ष ने बताया कि इन दोनों आवासीय योजनाओं में लैंड पूलिंग, किसानों से सहमति के आधार पर क्रय एवं अर्जन के तहत भूमि जुटाव किया जाना है। वर्तमान में लैंड पूलिंग नीति के तहत जमीन के एग्रीमेंट किये जा रहे हैं। इस बीच संज्ञान में आया कि कुछ निवेशक व रियल एस्टेट कारोबारी योजना में विकसित भूखण्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे मूल भू-स्वामियों के हित प्रभावित होने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होने की आशंका थी। इसे ध्यान में रखते हुए धारा-11 की अनिवार्यता का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिस पर शासन ने भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

मूल भूमि-स्वामियों को मिलेगा लाभ

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दोनों योजनाओं में लैंड पूलिंग का विकल्प खुला रहेगा। हालांकि, लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत केवल उन्हीं भू-स्वामियों को लाभ प्राप्त होगा, जिनका नाम वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि खरीदने वाले किसी भी नए व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

इन गांवों में लागू हुयी धारा-11

आईटी सिटी योजना में प्रथम चरण में 686.66 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकास कार्य किये जाएंगे। जिसके लिए तहसील-मोहनलालगंज के अंतर्गत ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली एवं भटवारा की भूमि पर धारा-11 लागू की गयी है। वहीं, वेलनेस सिटी में प्रथम चरण में 485 हेक्टेयर क्षेत्रफल में योजना विकसित की जाएगी। जिसके लिए ग्राम-बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा एवं मस्तेमऊ की भूमि पर धारा-11 लागू की गयी है।■

आवरण कथा

विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा

प. बंगाल की राह पर यूपी!

रामेन्द्र सिन्हा

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ रहा है। तेल-गैस संकट के बीच बढ़ती महंगाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण ने जहां विपक्ष के तेवरों में प्राण फूंक दिये हैं, वहीं हिंदुत्व के ब्रांड एंबेसडर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि तले भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत की आशा लगाए बैठा है। यही नहीं, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण में 2 करोड़ से अधिक अवैध वोटों के हटने और लाखों नए युवाओं के जुड़ने से नतीजे पूरी तरह अप्रत्याशित हो सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

राम मंदिर भाजपा की राजनीति का आधार स्तंभ रहा है, इसलिए मंदिर के दानपात्र (चढ़ावे) से करोड़ों रुपये की चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के विवाद से उसे सबसे ज्यादा रक्षात्मक होना पड़ा है। जबकि, सपा, कांग्रेस और आप सहित विपक्षी दलों के लिए अयोध्या में जमीन खरीद विवाद के बाद यह मामला सत्ता पक्ष को घेरने का एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। विपक्ष इस मुद्दे को "भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात" और "भगवान के घर में लूट" के रूप में प्रचारित कर रहा है, जिससे भाजपा की 'ईमानदार और धार्मिक' छवि को धक्का लगा है। न्यास के शीर्ष पदाधिकारियों जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा पर इस विवाद की आंच और फिर

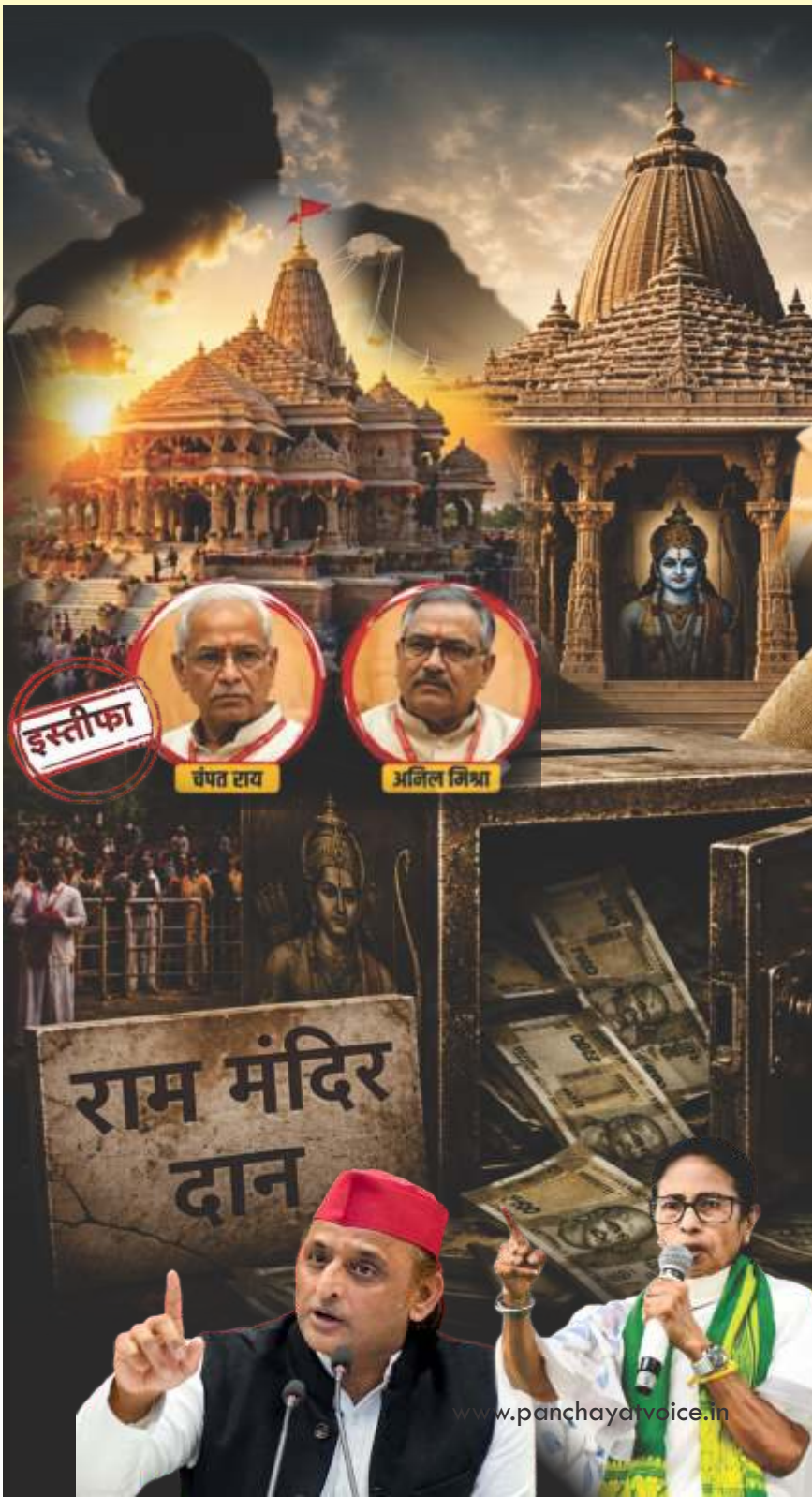

त्यागपत्र यह दर्शाता है कि विवाद की छाप गहरी है और सरकार व प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर बेहद गंभीर हैं। विपक्ष द्वारा इसे "छोटी मछलियों को फंसाने" और "महानुभावों को बचाने" की कोशिश बताकर न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ द्वारा न्यास के अनुरोध पर तुरंत एसआईटी का गठन, त्वरित जांच, नकदी की बरामदगी और आरोपियों को जेल भेजना सरकार की "जीरो टॉलरेंस" नीति को दिखाता है। भाजपा बताना चाहती है कि वे गड़बड़ी करने वालों को बख्श नहीं रहे हैं, चाहे वे कोई भी हों। न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त किया है कि जिन्होंने चांदी की इंटें, आभूषण आदि प्रभु श्रीराम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी हैं, वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। अब यदि योगी सरकार की एसआईटी जांच में छोटे-बड़े सभी दोषी कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो विपक्ष का यह मुद्दा बेअसर हो सकता है। विपक्ष पर मामले को "राजनीतिक रंग" देने और "सनातन को बदनाम करने" के आरोप भी सत्ता पक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो विपक्ष के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

यही नहीं इसके पहले, वैश्विक तेल-गैस संकट के कारण घरेलू बाजार में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दामों और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में आए भारी उछाल से उपजी महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस जनता के बीच आक्रामक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ने से सीधे तौर पर माल ढुलाई महंगी हुई है, जिससे फल, सब्जियां, दूध और दैनिक राशन की कीमतें बढ़ गई हैं। विपक्ष इसका इस्तेमाल भाजपा के सबसे मजबूत कोर वोटर यानी 'शहरी मध्यम वर्ग' को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहा है। डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ी है। अखिलेश यादव द्वारा "300 यूनिट मुफ्त बिजली और रियायती दरों पर ईंधन" का वादा सीधे तौर पर भाजपा के ग्रामीण जनाधार को चोट पहुंचा रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से स्थानीय होटल, ढाबा, चाय स्टाल और बेकरी चलाने वाले छोटे कारोबारियों का बजट बिगड़ा है। डैमेज कंट्रोल के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के शीर्ष नेता जनता के बीच लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि ईंधन की कीमतों में यह वृद्धि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (जैसे मिडिल ईस्ट संकट) के कारण है, न कि घरेलू नीतियों के कारण। भारत सरकार द्वारा वैश्विक दबाव के बावजूद डोमेस्टिक एलपीजी (घरेलू गैस सिलेंडर) की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखने के तर्क को भाजपा अपनी 'जन-हितैषी' छवि के रूप में पेश कर रही है।

भाजपा सरकार 'मुफ्त राशन योजना' और विभिन्न डीबीटी योजनाओं के जरिए गरीब वर्ग को एक सुरक्षा कवच दे रही है। यह गरीब तबका महंगाई से परेशान होने के बावजूद 'नमक का हक' और 'मुफ्त अनाज' के कारण भाजपा के साथ लामबंद रह सकता है, जिससे विपक्ष का प्रभाव ग्रामीण गरीबों में सीमित हो जाता है। हालांकि, विपक्ष महंगाई के साथ बिजली कटौती, पेपर लीक और बेरोजगारी को जोड़कर 'युवा विरोधी सरकार' का माहौल भी बनाने से नहीं चूक रहा है।

योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सुधरी कानून व्यवस्था, माफियाओं पर नकेल और धार्मिक त्योहारों (जैसे बकरीद पर खुले में नमाज या अवैध कुर्बानी पर रोक) के कड़े नियमों को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। बिजली कटौती के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके कार्यकाल में बिजली के तारों पर लोग कपड़े सुखाया करते थे। विपक्षी दल दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटों को साधने के लिए आरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस और सपा इस वर्ग में पैठ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, गठबंधन में साथ होने के बावजूद कांग्रेस और सपा के बीच जुबानी जंग भी जारी है। सपा खुद को 'आम का पेड़' और कांग्रेस नेता खुद को 'बरगद का पेड़' बताकर अपना जनाधार बड़ा सिद्ध करने में लगे हैं।

लोकसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित

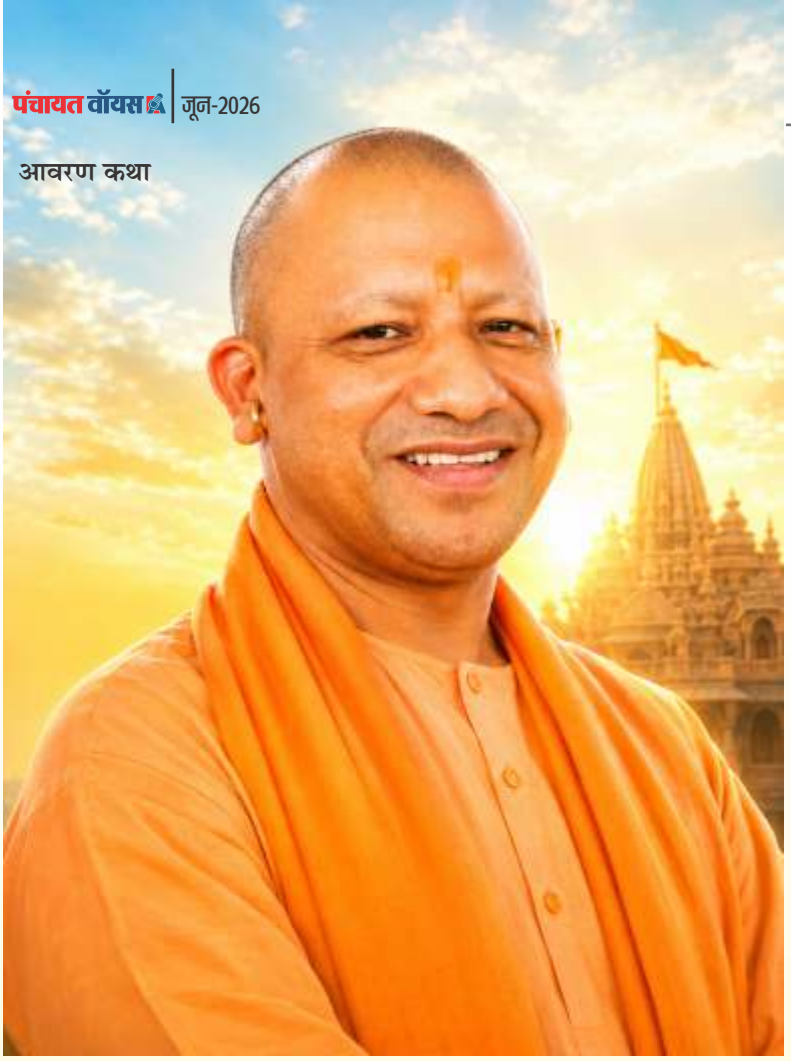

सहयोगी दलों के नेतृत्व ने स्वयं कमान संभाल ली है। भाजपा ने प्रदेश में अपने सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया है। नई गठित 64 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी में 25 से अधिक सदस्य गैर-यादव ओबीसी समुदाय से बनाए गए हैं ताकि विपक्ष के जातीय समीकरण को काटा जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सीधे जुड़ाव के लिए 'योगी की पाती' नाम से एक विशेष पत्र अभियान शुरू किया है। वे लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों का आक्रामक दौरा कर रहे हैं। भाजपा ने राज्य की उन 60 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां पार्टी कमजोर रही है। इन सीटों पर बड़े नेताओं को तैनात कर 'सोशल इंजीनियरिंग' का नया गणित बिठाया जा रहा है। योगी सरकार कानून-व्यवस्था और 'बुल्डोजर नीति' के साथ-साथ अब एक्सप्रेस-वे (जैसे गंगा एक्सप्रेस-वे), निवेश और युवाओं के लिए रोजगार जैसे आर्थिक सुधारों को मुख्य एजेंडा बना रही है। उधर, उप्र के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने नई बहस छेड़ दी है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी के कई सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। राजभर ने एक बड़ा सियासी धमाका करते हुए आरोप लगाया कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने इस संभावित टूट से संबंधित एक गोपनीय चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। राजभर ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि "अगर हिम्मत है तो अपनी पार्टी को टूटने से बचाकर दिखाएं"। दूसरी ओर, "निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भी दावा किया कि सपा और कांग्रेस के लगभग दो दर्जन से ज्यादा सांसद और कई विधायक उनके सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के भीतर मौजूद 'हिंदुत्व विचारधारा' वाले नेताओं का दम घुट रहा है। उन्हें लगता है कि विपक्ष में रहकर वे जनता को संवैधानिक अधिकार और सम्मान नहीं दिला सकते, इसलिए वे सत्ता पक्ष के साथ जुड़कर दिल्ली-लखनऊ की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं। निषाद ने कहा कि जैसे-जैसे निषाद और अन्य पिछड़ी जातियां जागरूक हो रही हैं, वैसे-वैसे सपा की जमीन खिसक रही है। सपा और कांग्रेस के अनुसार, राजभर और निषाद यह माहौल सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आगामी चुनाव में भाजपा से ज्यादा से ज्यादा सीटों की सौदेबाजी कर सकें।

दूसरी ओर, 2024 की सफलता को दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा के बड़े 'हिंदू नैरेटिव' को तोड़ने के लिए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) और जातिगत जनगणना का कार्ड खेला है। इस कारण से हिंदू मतदाता के धार्मिक पहचान से ज्यादा अपनी जातीय पहचान (जैसे यादव, कुर्मी, मौर्य, दलित) के आधार पर बंटने का अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अंदरूनी मोर्चे पर दोनें पार्टियों में खींचतान जारी है। जबकि, बसपा अकेले दम पर अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक के साथ सवर्णों को फिर से एकजुट करने की कोशिश में है। बसपा प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर विपक्ष, विशेषकर सपा की चिंता बढ़ा दी है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण में राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 2 करोड़ 4 लाख फर्जी, मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इससे चुनाव में होने वाली 'फर्जी या फर्जी वोटिंग' की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान 84 लाख से अधिक नए और योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। यह युवा वर्ग किसी भी दल की पारंपरिक 'जातिगत लामबंदी' (जैसे सपा का पीडीए या बसपा का दलित कार्ड) से बंधा हुआ नहीं है। युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार, पेपर लीक विरोधी कड़े कानून, और डिजिटल सुविधाएं मुख्य चुनावी एजेंडा बन रही हैं। नई सूची के बाद प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। यह 'साइलेंट महिला वोट बैंक' कानून-व्यवस्था और सरकारी राशन/डीबीटी योजनाओं के आधार पर मतदान करता है, जिसका सीधा फायदा अतीत में भाजपा को मिलता रहा है। हालांकि, विपक्ष भी अब अपनी रैलियों में महिलाओं के लिए विशेष भत्तों की घोषणाएं कर रहा है। इस गहन मतदाता पुनरीक्षण ने उत्तर प्रदेश के जातीय और क्षेत्रीय चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। जिन सीटों पर पहले 2,000 से 5,000 वोटों के अंतर से हार-जीत होती थी, वहां 2 करोड़ से अधिक अवैध वोटों के हटने और लाखों नए युवाओं के जुड़ने से नतीजे पूरी तरह अप्रत्याशित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ■

पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां

यूपी पंचायत चुनाव @ 12.58 करोड़ मतदाताओं के साथ जारी हुई अंतिम वोटर लिस्ट

पांच साल में 29 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े, पुनरीक्षण में 2.32 करोड़ नाम शामिल किए गए और 2.03 करोड़ नाम हटाए गए

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। वर्ष 2026 की पंचायत चुनाव मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 12 करोड़ 58 लाख 51 हजार 570 मतदाता दर्ज किए गए हैं। यह संख्या वर्ष 2021 की पंचायत मतदाता सूची में दर्ज 12 करोड़ 29 लाख 50 हजार 52 मतदाताओं की तुलना में 29 लाख 1 हजार 518 अधिक है। अंतिम सूची जारी होने के साथ ही पंचायत चुनाव की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर नए मतदाताओं को जोड़ा गया और मृत, स्थानांतरित अथवा अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया में 2 करोड़ 32 लाख 24 हजार 805 नए नाम सूची में शामिल किए गए, जबकि 2 करोड़ 3 लाख 23 हजार 287 नाम हटाए गए। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश की कुल मतदाता संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

इस बार मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। इसी प्रक्रिया में करीब 1.41 करोड़ नाम सूची से हटाए गए तथा मतदाताओं की पहचान को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए नौ अंकों की पहचान प्रणाली को भी लागू किया गया है। चुनावी प्रक्रिया को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जौनपुर प्रदेश का सबसे बड़ा मतदाता जिला बनकर सामने आया है। यहां कुल 36 लाख 97 हजार 376

मतदाता दर्ज किए गए हैं। प्रयागराज में 34 लाख 95 हजार 203, सीतापुर में 31 लाख 18 हजार 29, गोरखपुर में 29 लाख 63 हजार 142 तथा लखीमपुर खीरी में 28 लाख 87 हजार 290 मतदाता हैं। इसके अलावा हरदोई में 28.73 लाख, गाजीपुर में 28.11 लाख, बलिया में 26.97 लाख, गोंडा में 26.74 लाख तथा बाराबंकी में 23.20 लाख से अधिक मतदाता दर्ज किए गए हैं।

मतदाता वृद्धि के मामले में लखीमपुर खीरी प्रदेश में सबसे आगे रहा है। यहां 1 लाख 38 हजार 223 नए मतदाता बढ़े हैं। बलिया में 1 लाख 60 हजार 376, देवरिया में 1 लाख 26 हजार 771, सिद्धार्थनगर में 1 लाख 23 हजार 162 तथा कुशीनगर में 1 लाख 20 हजार 11 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में भी मतदाता संख्या बढ़ी है। यहां अंतिम सूची के अनुसार कुल 10 लाख 85 हजार 80 मतदाता दर्ज किए गए हैं और पुनरीक्षण के बाद 30 हजार 51 नए मतदाता जुड़े हैं।

दूसरी ओर कुछ जिलों में मतदाताओं की संख्या में कमी भी दर्ज की गई है। आगरा में 23 हजार 294, आजमगढ़ में 60 हजार 347, गाजीपुर में 94 हजार 757, मैनपुरी में 93 हजार 207 तथा महोबा में 16 हजार 962 मतदाताओं की शुद्ध कमी दर्ज हुई है। खास बात यह है कि गाजीपुर कुल मतदाताओं की संख्या के लिहाज से प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन पुनरीक्षण के बाद वहां मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी भी सामने आई है।

उधर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारण प्रदेश में पहली बार 57 हजार 694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया गया है। सरकार ने इनके कार्यों और अधिकारों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निवर्तमान प्रधान 27 मई से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं।

नए शासनादेश के अनुसार अब कोई भी प्रशासक अपनी ओर से नया विकास कार्य शुरू नहीं कर सकेगा। किसी भी नए कार्य के लिए उसे जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजना होगा। जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही नया कार्य शुरू कराया जा सकेगा। यानी ग्राम पंचायतों में अब नए विकास कार्यों पर अंतिम निर्णय डीएम स्तर से लिया जाएगा। हालांकि प्रशासक बनाए जाने से पहले स्वीकृत, अनुमोदित, निर्माणाधीन, मरम्मताधीन अथवा पूर्ण हो चुके कार्यों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ऐसे कार्यों का भौतिक और तकनीकी मूल्यांकन कराकर पूर्व की तरह भुगतान किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और प्रशासनिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज होने की संभावना है। बढ़ी हुई मतदाता संख्या, नए वोटरों की बड़ी भागीदारी और ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था लागू होने से इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में अलग और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।■

शिक्षक भर्ती

राम जी का वनवास तो 14 वर्ष में पूरा हो गया था

शिक्षक चयन भर्ती के अभ्यर्थियों का वनवास अभी जारी है

बसपा के शासन में 2011 में आई थी भर्ती, फिर सपा की सरकार बनी और अब भाजपा का शासन, न्याय की आस में कोर्ट में मिल रही तारिख

सौम्या द्विवेदी

भारत में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह सरकारी नौकरी और परीक्षाओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, वह बहुत गंभीर है। अब तो युवा यह मानने लगे हैं कि नौकरी के लिए पढ़ना, परीक्षा देना और परिणाम आने तक के ही स्तर नहीं है, बल्कि इसमें पेपर लीक होना और सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाना भी शामिल है। इसलिए यदि सरकारी नौकरियों के चक्कर में है तो संभल जाइए। यह हालांकि तंज है, मगर गलत भी नहीं है। तमाम ऐसे उदाहरण है, जिनमें व्यवस्थागत खामियों की वजह से यहाँ भर्तियां समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने को विवश हैं। वो भी तब जब हम पूरी दुनियाँ में विश्वगुरु बनकर निरंतर अपनी पीठ थपथपाते आ रहे हैं। अब तो यह माना जाने लगा है कि ये भर्तियां चुनाव में वोट पाने का एक जरिया हैं और उसमें समस्याएं जानबूझकर उत्पन्न की जाती हैं, ताकि लंबे समय तक परीक्षार्थी कोर्ट में उलझे रहें। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि सरकार अब नौकरी देना ही नहीं चाहती।

यहां हम जिस भर्ती की बात कर रहे हैं उसको शुरू हुए राम जी के वनवास से भी लंबा समय हो गया, क्योंकि राम जी का वनवास तो 14 वर्ष में पूरा हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा के शासन के दौरान 2011 में आई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक चयन भर्ती का जो वनवास है वह अभी तक चल रहा है। दुःखद ये कि कुछ अभ्यर्थी तो नौकरी का इंतजार करते-करते इस धरती को भी अलविदा कर गए। बात शुरू होती है 30 नवंबर 2011 से जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती हेतु एक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन मांगे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में टेट 2011 भर्ती, जिसमें जिलावार 72825 शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी। इस तरह से यह एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया थी। इसका आधिकारिक विज्ञापन जो 2011 में जारी हुआ जिसमें चयन टेट के अंकों पर होना था लेकिन बाद में जिस तरह भर्ती के नियमों में बदलाव, जटिल कानूनी प्रक्रिया,भर्ती प्रक्रिया में संशोधन, याचियो और मुकदमों में उलझाया गया। उसने हजारों अभ्यर्थियों को निराशा के गहरे अंधकार मे डूबो दिया।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इस प्रशिक्षण के लिए अहर्ताएं तय की गई, साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में ₹500 का बैंक ड्राफ्ट सामान्य के लिए और ₹ 200 का अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए तय किया गया। इसके अलावा कुल व्यक्तियों के सापेक्ष 10% रिक्तियां सुरक्षित रखी गई शिक्षामित्रों के लिए।

30 -11 -2011 की नियुक्ति को हाई कोर्ट इलाहाबाद में चुनौती दी गई कि पांच ही जिलों में आवेदन क्यों किया गया?,और ₹500 का बैंक ड्राफ्ट एक से अधिक जिले में क्यों भेजा जाए? इस पर हाई कोर्ट इलाहाबाद नें आदेश जारी किया कि किसी एक जनपद के बैंक ड्राफ्ट को मूल बैंक ड्राफ्ट मानकर सभी जनपदों में उसकी छाया प्रति भेज कर आवेदन करें। अभ्यर्थियों नें यही किया लेकिन बाकी जिलों में जो 500 के पांच बैंक ड्राफ्ट अभ्यर्थियों ने भेजें उनका कोई पता ठिकाना नहीं, वह पैसा उनका कहाँ गया।

इसके बाद बसपा का शासन खत्म होने और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस विज्ञापन को ही निरस्त कर दिया गया। नया विज्ञापन जारी करते हुए टेट मेरिट को ही अंतिम रूप से चयन का आधार बनाया। अब यहीं से अभ्यर्थियों को परेशान करने का एक काम शुरू हो गया।

30-11-2011 की विज्ञप्ति में जो चयन टेट के अंको पर होना था उस भर्ती प्रकिया को ही 07-12-2012 के विज्ञापन में बदल दिया गया। अब चयन हाई स्कूल से लेकर स्नातक बीएड के प्राप्तांक के गुणांक के आधार पर तय कर दिया।

सपा सरकार ने चयन प्रक्रिया को बदल कर इसे शैक्षणिक गुणांक के आधार पर करने का निर्णय

लिया और एक दिन काउंसलिंग भी कर ली गई। सरकार के इस निर्णय को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा इस विषय पर तथ्यात्मक दलील ना पेश करने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन को निरस्त कर दिया और पुनः मूल विज्ञापन को बहाल किया, जिस पर सपा सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट नें भी इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया, और कहा कि पहले से बनाए नियमों को बीच में बदला नहीं जा सकता।

अंततः यह भर्ती 30 /11 /2011 के ही विज्ञापन के आधार पर शुरू करना पड़ा जिसके तहत 17 /12/ 2014 तक 54464 पद भरे गए। फिर अचानक चयन प्रक्रिया रुक गई। प्रकिया रुकने पर जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई में सरकार से प्रश्न पूछा गया कि चयन प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी, तब राज्य सरकार ने 14640 रिक्त पदों का हवाला देते हुए माननीय न्यायालय को बताया कि सरकार नियुक्ति देने के लिए बुला रही है मगर लोग आ ही नहीं रहे हैं । तब इन 14640 पदों पर नियुक्ति का क्राईटेरिया तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 70% और आरक्षित वर्ग के लिए 65 प्रतिशत टेट अंक तय किया एवं उस क्राइटेरिया में आने वाले अभ्यार्थियों से प्रत्यावेदन लेने और उन्हें नियुक्त करने का निर्देश दिया।

इसके लिए सरकार को एक सूची बनाने का भी निर्देश दिया गया इसके बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए टीईटी के लिए निर्धारित अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया और 16/11/2015 तक डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भेजनें के लिए कहा।

इस विज्ञापन के उपरांत 16/11/2015 तक 75612 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें से 3149 आवेदन खारिज कर दिए गए और 72463 प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया जिसमें से 12091 अभ्यर्थियों को छांटा गया।

सरकार के अनुसार यह 12091 अभ्यर्थी कट ऑफ मेरिट से ऊपर थे और एक या दो जिलों की कट ऑफ मेरिट से ऊपर उनके अंक थे। टेट अनुक्रमांक और एससीइआरटी के द्वारा दिए गए मास्टर डाटा की सूचना के आधार पर इन अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह कौन-कौन से जनपद थे। ध्यान देने योग्य है कि इस सूची को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधान सहायक, उपसचिव, संयुक्त सचिव एवं सचिव जैसे उच्च पदाधिकारियो ने हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित भी किया। जिसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 /12 /2015 को आदेश देते हुए इन 12091 अभ्यर्थियों को 6 सप्ताह के भीतर जांच कर नियुक्ति देने का आदेश दिया।

"12091 की सूची जिसमें इस भर्ती के लिए उचित और इसके सभी मानको को पूरा करने वाले योग्य उम्मीदवार हैं और जिसे खुद अधिकारियों नें प्रमाणित किया है, वे लम्बे समय से इस नियुक्ति के लिए उम्मीद बांधे हुए संघर्ष कर रहे है। ये दुर्भाग्य है कि इनके संघर्ष को सत्ता और व्यवस्था संवेदना और न्याय की दृष्टि नहीं देख रही । ये सत्य की लड़ाई है अधिकार की लड़ाई है। जिस नौकरी को पाने के लिए हम आर्थिक,मानसिक हर तरह का संघर्ष कर रहे है वो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए।" -राम प्रसाद विश्वकर्मा, याचिकाकर्ता

"12091 सूची के अभ्यार्थी आज भी दर दर भटक रहे हैं इनको न्याय नहीं मिल पा रहा हैं। कंटेंप ऑफ़ कोर्ट हुआ है लेकिन आज तक न्याय से वंचित है। आर्थिक शोषण,न्यायालय की लंबी प्रक्रिया और बेरोजगारी से लड़ते हुए कई साथी तो यह दुनिया ही छोड़ चुके है और कुछ साथी आज भी इसी उम्मीद में लड़ रहे हैं क्युकि उन्हें यह विश्वास है कि सत्य की सदा ही जीत होती है। बस इसी हौसले पर हम आगे बढ़ रहे हैं।" -हरिओम सिंह जादौन, मुख्य याची

उस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 14640 रिक्तियां दिखाई थी और 12091 योग्य अभ्यर्थी थे और इनमें से केवल 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। 3/2/2016 को एक काउंसलिंग करने का मौका दिया लेकिन उसमें 12091 के अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए इसलिए 12091 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई।

इससे पहले 7 /12 /2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरे पार्ट में 1100 याचियों में से 862 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया था। इन 862 में 840 लोगों की नियुक्ति दे दी गई थी और मजेदार बात जिसे जानकर आप चौंक जायेंगे वो ये है कि इनको बिना वेरिफिकेशन किए हुए एडहॉक पर नियुक्ति दी गई। इन 862 में से 95 अभ्यर्थी ऐसे थे, जो 30 /11 /2011 के विज्ञापन में आवेदन ही नहीं किए थे, लेकिन नियुक्ति पा गए थे।

इसके अलावा सामान्य वर्ग के 80 ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली जो 70% निर्धारित अंक टेट में प्राप्त नहीं कर पाए थे। यही हाल आरक्षित वर्ग में था जिसमें 171 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 60% अंक टेट में प्राप्त नहीं किए थे। 27 ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली जो बेसिक नियमावली को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे यानी कि जिनके 45% अंक भी नहीं थे।

2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इन अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी मगर,उत्तर प्रदेश बनाम शिवकुमार पाठक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी अंक को अंतिम योग्यता सूची मानने की जगह केवल एक अहर्ता परीक्षा ठहरा दिया।

13 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा सरकार द्वारा अपनाई गई नियुक्ति प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण मानते हुए इसे न्यायालय की अवमानना बताया था,उस अवमानना याचिका पर सुनवाई कर न्यायालय नें सरकार द्वारा अपनई गई नियुक्ति प्रक्रिया को सही ठहराया और उसमें किसी भी तरह की गलती न मानते हुए याचिकाओं को निरस्त कर दिया।

इसी बीच जनवरी 2024 में 12091 सूची के याचियों के पक्ष को सुनते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल बेंच ने 12091 अभ्यर्थियों के लिए फिर से विज्ञापन निकालकर उन्हें निर्धारित समय में नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया। इससे कुछ समय के लिए इन अभ्यर्थियों में उल्लास तो आया लेकिन वह जल्दी समाप्त हो गया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही डबल बेंच नें फैसले पर यूटर्न लेकर ये कहते हुए एकल

शिक्षक भर्ती

बेंच के आदेश को रद्द कर दिया कि " बहुत लम्बे समय से यह प्रक्रिया चल रही है और 13 वर्ष का बहुत लंबा समय बीत जाने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। यह निर्णय देकर एकल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया गया। इससे अभ्यर्थी घोर निराशा में चले गए क्योंकि उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह सरकार की अक्षमता थी, व्यवस्था की लापरवाही, न्यायपालिका की पराजय थी या उनका दुर्भाग्य। क्योंकि अभ्यर्थियों के अनुसार वह अपने हक की वाजिब लड़ाई लड़ रहे थे और कमियां व्यवस्थागत थीं, वे केवल स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। हताश निराश अभ्यर्थी जब अपनी गुहार लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी डबल बेंच की ही बात को सामने रखते हुए 12091 की नियुक्ति की याचिका को खारिज कर दिया। इसी क्रम में 2025 में प्रशांत शुक्ला को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए याचियों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, जो 2017 से पहले की सूची में भी शामिल थे और वर्तमान अवमानना सूची में भी। इस क्रम में अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या का आंकलन करने के लिए 14851 याचियों की सूची सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई। वहीं फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि 72825 पदों के मुकाबले कुल 66655 भरे जा चुके हैं और वर्तमान में केवल 4465 पद हैं, जो आरक्षित वर्ग के हैं। सरकार का यह भी कहना है कि 2017 के बाद से 126371 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। यहाँ एक रोचक बात याचियों की तरफ से उठाई गई, क्योकि सरकार के पक्ष को मानें तो 54464 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बाद के 14640 रिक्त पद थे, इसी रिक्तियों के सापेक्ष 12091 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना था, लेकिन 12091 में से केवल 400 अभ्यथियों को नियुक्ति दी तो यहाँ तक कुल संख्या-54864 हुई। तो सरकार का आंकड़ा 64257 पर कैसे पहुँच गया?, यह प्रश्न कौतुहल पैदा करता है क्योंकि 54464 में 12091 को जोड़ दें तो यह संख्या 66655 पहुँचती है। प्रश्न तो उठेंगे ही। मार्च 2026 में इस केस की विस्तृत पृष्ठभूमि को देखते हुए इसे पांच अलग-अलग श्रेणीयों में बांटा गया, ताकि इसकी श्रेणीवार समीक्षा की जा सके। इसी क्रम में मई 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने 'याची लाभ' देने के लिए तीन शर्तें रखी जिसमें वे लोग जिन्होंने 2011 में फॉर्म भरा था, 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं, एवं दिसंबर 2025 तक अवमानना याचिकाओं का हिस्सा रहे हैं, शामिल होंगे। इस आधार पर योग्य विद्यार्थियों की संख्या लगभग 11000 के आसपास आ रही है। अभ्यर्थी लगातार न्यायालय के सामने गुहार लगा रहे हैं कि न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए योग्य याचियों को उनका अधिकार दे। यहां उम्मीद की एक किरण बन रही थी कि शायद इस मामले पर निर्णायक सुनवाई हो जाएगी, लेकिन 26 मई 2026 को इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस करोल और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की बेंच नें इसे दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। स्पष्ट है कि अब नई बेंच मामले को नए सिरे से सुनेगी और न्याय की आस में वर्षों से बैठे हुए इन अभ्यार्थियों का इंतजार और बढ़ गया। अब सब कुछ सरकार के विवेक और उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर है, क्योंकि दोष कहीं भी हो यह तो तय है कि न्याय की आस में बैठे यह हजारों अभ्यर्थी निरपराध है।■

तीन तलाक और एसिड पीड़िताओं को बड़ी राहत

सीएम योगी के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग तैयार कर रहा शासनादेश

पंचायत वॉयस, लखनऊ

योगी सरकार ने तीन तलाक तथा एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करने की तैयारी कर रही है। निराश्रित महिलाओं को भी इन सभी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग द्वारा तीन तलाक एवं एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के साथ निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डाटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके। दिशा-निर्देश और शासनादेश जीओ तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। महिला कल्याण विभाग द्वारा पीड़ित महिलाओं का सत्यापित विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ दिया जाए।

मालमू हो कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता थी। तीन तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं। ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों उपलब्ध कराकर योगी सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।■

पहल

यूपी में जमीन और मकानों को मिलेगी डिजिटल पहचान

रजिस्ट्री के साथ ही शुरू होगा नामांतरण

हर संपत्ति को यूनिक प्रापर्टी आईडी और हर भूखंड को 'भू-आधार' नंबर दिया जाएगा

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार भूमि और संपत्ति से जुड़ी व्यवस्थाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कुछ दिन पूर्व हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने व्यापक सुधारों का ऐसा खाका प्रस्तुत किया, जिसके लागू होने के बाद संपत्ति के पंजीकरण, स्वामित्व सत्यापन और नामांतरण की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।

बैठक में पंजीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत अधिनियम में नई धारा 22-ए, 22-बी और 35-ए जोड़े जाने की तैयारी है। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद किसी भी अचल संपत्ति के पंजीकरण से पहले उसके स्वामित्व और अधिकारों की पूर्व जांच अनिवार्य होगी। इससे फर्जी दस्तावेजों, विवादित संपत्तियों और स्वामित्व संबंधी धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संपत्तियों के लिए यूनिक प्रापर्टी आईडी विकसित करेगी। इस आईडी को जीआईएस मैपिंग और आधिकारिक स्वामित्व अभिलेखों से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से किसी भी संपत्ति की पहचान, मालिकाना हक, स्थिति और उससे जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे नागरिकों, निवेशकों और सरकारी विभागों को सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्राप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी तैयार करने का कार्य पहले से जारी है। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को यूनिक प्रापर्टी आईडी विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकार का उद्देश्य राज्य की प्रत्येक संपत्ति को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना है।

प्रस्तावित व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग से आवेदन करने या विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। विभिन्न विभागों के अभिलेखों का एकीकरण, एपीआई आधारित डेटा साझाकरण और रियल-टाइम रिकॉर्ड अपडेट प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे सभी रिकॉर्ड एक साथ अपडेट होते रहेंगे।

भूमि प्रबंधन को और अधिक सटीक बनाने के लिए प्रत्येक भूमि पार्सल को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी 'भू-आधार' प्रदान किया जाएगा। यह विशेष पहचान संख्या भूमि अभिलेखों को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीआईएस प्रणालियों से जोड़ने का आधार बनेगी। इससे भूमि संबंधी रिकॉर्ड अधिक सटीक, प्रमाणिक और अद्यतन बने रहेंगे।

नई व्यवस्था के तहत संपत्ति कर रजिस्टर को भी स्टांप एवं पंजीकरण विभाग, राजस्व विभाग, बिजली, पानी और सीवर विभागों के रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। कॉमन प्रापर्टी आईडी आधारित यह प्रणाली विभिन्न विभागों के बीच डिजिटल डेटा साझा करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कर संग्रहण व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और व्यवस्थित हो सकेगी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल एकीकरण और रिकॉर्ड के रियल-टाइम अपडेट से संपत्ति संबंधी विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी। स्वामित्व संबंधी अस्पष्टता दूर होगी, निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। योगी सरकार की यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को नई मजबूती देने के साथ-साथ प्रदेश में 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को भी नई गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।■

उत्तर प्रदेश

विकास के नए कीर्तिमान रच रहा उत्तर प्रदेश

- सीएम योगी ने यूपी को 3 महीने में दी 62 हजार करोड़ से अधिक की 5,551 परियोजनाओं की सौगात
- शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन समेत अन्य सेक्टरों को मिली नई गति, विकास की पहचान बना यूपी
- हर जिले में विकास, हर क्षेत्र में निवेश से उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को करेगा हासिल
- पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल समेत प्रदेश के सभी जनपदों को विकास से जोड़ने पहुंच रहे सीएम योगी

पंचायत वॉयस, लखनऊ

बीते 9 साल से निरंतर विकास की बुलंदियों को छू रहा उत्तर प्रदेश नित नए कीर्तिमान रच रहा है। यदि वित्तीय वर्ष 2026-27 की बात करें तो पहली तिमाही में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर जनपदों के दौरे कर विकास की सौगात दे रहे हैं। वे पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, मध्याचंल समेत प्रदेश के सभी जनपदों को विकास से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल, मई और जून के दौरान प्रदेशभर में आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, खेल, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी से जुड़ी 5,551 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 62,282 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जो प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर तेजी से क्रियान्वित हो रहा है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

हर क्षेत्र में विकास की समान गति

इन तीन महीनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज, खेल अवसंरचना, औद्योगिक पार्क, नगर विकास, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और डिजिटल सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। योगी सरकार ने केवल बड़े शहरों पर ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र के जिलों में भी विकास कार्यों को समान प्राथमिकता दी।

गंगा एक्सप्रेसवे पर दौड़े विकास के पहिए, जेवर से हुई प्रगति की उड़ान

इस अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले गंगा एक्सप्रेसवे व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का लोकार्पण रहा। मेरठ से प्रयागराज तक प्रदेश को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं नोएडा

www.panchayatvoice.in

हक़ीक़त परत दर परत

इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से भी प्रगति की उड़ान हुई। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान पहली फ्लाइट में बैठकर लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद भी किया।

शिक्षा और तकनीक पर विशेष जोर

योगी सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक तकनीकी शिक्षा को भी प्राथमिकता दी। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और थ्री-डी प्रिंटिंग जैसे भविष्य की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में भी सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना के माध्यम से युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार

योगी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भी अनेक परियोजनाओं की शुरुआत की। ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित स्वास्थ्य अवसंरचना से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। विभिन्न जिलों में अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

उद्योग और निवेश को नई ऊर्जा

ललितपुर में 1,500 एकड़ में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक सुविधाओं और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से निवेश के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

सांस्कृतिक विरासत को मिला बढ़ावा

प्रदेश सरकार पर्यटन विकास को भी प्राथमिकता दे रही। संतकबीर नगर में तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, बाबा बैजूनाथ धाम के विकास और बखिरा झील को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। महोबा को एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके साथ ही प्रदेशभर में इको टूरिज्म को लेकर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है।

खेल और शहरी सुविधाओं का विस्तार

गोरखपुर में लगभग 393 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया, जिसमें 30 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। वहीं नगर निगमों में आधुनिक सदन भवन, मल्टीलेवल पार्किंग, टू-लेन ब्रिज, ईको पार्क और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास से नागरिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया।

सामाजिक समरसता और जनकल्याण को भी प्राथमिकता

लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों, पीलीभीत में हजारों बंगाली परिवारों को नागरिकता और भूमि अधिकार पत्र वितरित किए गए। इस तरह प्रदेश में कई अवसरों पर लोगों को नियुक्ति पत्र व अन्य सुविधाओं से जुड़े पत्र भी वितरित किए गए। वहीं श्रमिक कल्याण योजनाओं, कल्याण मंडपम और अन्य जनसुविधाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया।

विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव

इसी तरह रामपुर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, उन्नाव, आजमगढ़, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, ललितपुर और अन्य जिलों में सैकड़ों विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जिस गति से हजारों विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, उससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विकास अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर तेजी से क्रियान्वित हो रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, खेल और शहरी विकास जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में एक साथ हो रहे निवेश प्रदेश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं।

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निगरानी करते आ रहे हैं। वहीं एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, फार्मा पार्क और औद्योगिक क्लस्टर जैसी आधारभूत परियोजनाओं के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि, एमएसएमई, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति दी जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने, रोजगार सृजन, कौशल विकास और बेहतर कानून-व्यवस्था के माध्यम से उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य तेज आर्थिक विकास के साथ प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। ■

आकार ले रहा गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

पूर्वांचल को मिलेगी नई पहचान

निखिल पाण्डेय

गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्वांचल के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दंने के लिए आकार ले रहा है। यही नहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गोरखपुर को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने का माध्यम बनने की दिश में भी तेजी से बढ़ रहा है। अब वह दिन दूर नहीं कि गोरखपुर शहर की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर होगी। इससे

> - चंद दिनों में ही लगभग 6.73 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा, 30 हजार दर्शकों के बैठने की होगी व्यवस्था
> - खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा स्टेडियम परिसर
> - 392.94 करोड़ की लागत से बन रहा विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

पर्यटन, होटल, परिवहन और व्यापार क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी देगा। हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल अवसंरचना के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो तेजी से आकार ले रहा है। लगभग 392.94 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का करीब 6.73 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्टेडियम न केवल पूर्वांचल, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योगी सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित होगा। स्टेडियम का 16 मई 2026 को भूमिपूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मिट्टी भरने का काम पूरा हो गया है। पाइलिंग का

"गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्वांचल के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गोरखपुर को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने का माध्यम बनेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन एवं स्टेडियम परिसर में ही क्रिकेट अकादमी, कोचिंग और खेल संबंधी अन्य सुविधा मिलने के अलावा गोरखपुर शहर की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूत होगी और पर्यटन तथा होटल, परिवहन और व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
"- विशाल पांडेय, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, गोरखपुर

" गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने से गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों में हर्ष की लहर है। स्टेडियम बनने से अंतरराष्ट्रीय पहचान गोरखपुर की बनी है साथ ही साथ खेलों के प्रति लोगों में जागृति भी बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गोरखपुर के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है जिसका सकारात्मक असर आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखेगा
" -संजय साहनी, रेफरी, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ

" अब जबकि अभिभावक स्वयं बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूलों में खेल पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसे देखते हुए गोरखपुर में जिस तरह सरकार और प्रशासन द्वारा खेलकूद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है यह भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सुविधाओं से लैस अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनने से न सिर्फ गोरखपुर का नाम अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकेगा, बल्कि इससे अच्छे कोच, अच्छे खिलाड़ी और खेलकूद का एक अच्छा माहौल बनेगा। स्टेडियम बनने से बच्चे ग्राउंड से जुड़ेंगे, और गोरखपुर ही नहीं उसके आसपास के क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए ये उपलब्धि उत्सावर्धक है " -रीता मिश्रा, अंतराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं महिला हॉकी कोच

काम चल रहा है। खेल निदेशालय के मुताबिक, वर्तमान में स्टेडियम का भौतिक निर्माण कार्य लगभग 6.73 प्रतिशत पूरा हो चुका है और कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य 23 दिसंबर 2027 तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्ण करना है। करीब 46 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम 30 हजार दर्शकों की क्षमता वाला होगा।

गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों की भी मजबूत व्यवस्था की गई है। इस परियोजना हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में 63 करोड़ 39 लाख रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। इस खेल परिसर में खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेडियम का निर्माण ग्राउंड प्लस टू फ्लोर मॉडल पर किया जा रहा है। मुख्य मैदान में खिलाड़ियों के लिए सात प्लेइंग पिच और चार प्रैक्टिस पिच बनाई

जाएंगी। रात्रिकालीन मुकाबलों के आयोजन को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चार हाई मास्ट फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। इससे दिन-रात दोनों समय मैच आयोजित किए जा सकेंगे। स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अवसर भी प्राप्त होगा। इससे गोरखपुर की पहचान केवल धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में भी स्थापित होगी।

खेल सचिव सुहास एल. वाई. के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश में क्रिकेट हब के रूप में डवलप हो रहा है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी का काम पूरा होने की स्टेज पर है। इसी तरह गोरखपुर में निर्माण कार्य तेजी पर है और अयोध्या का स्टेडियम बनकर तैयार है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच हो रहे हैं। खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा कि गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से पूर्वांचल में खेलों को नई दिशा मिलेगी। गोरखपुर और आसपास के जिलों में क्रिकेट समेत अन्य खेलों की सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय खिलाड़ियों को अब अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।■

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा-गरीब, महिला, युवा व किसान को केंद्र में रखकर हुआ अभूतपूर्व विकास
- योगी ने कहा, विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प

12 वर्षों में बदला स्वरूप

विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा भारत

आदर्श श्रीवास्तव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है और आज देश का प्रत्येक नागरिक नए भारत का हिस्सा होने पर गर्व महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी व्यापक बदलाव हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आधार बनाकर अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसी के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर, वर्ष 2036 तक 2 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है। विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण ही प्रदेश का संकल्प है। यह प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों के प्रति उत्तर प्रदेश की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक योजनाएं बनती रहीं, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार योजनाओं को जन आंदोलन का स्वरूप मिला। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों बैंक खाते खोले गए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बने, 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने देश को नई दिशा दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की धुरी के रूप में गरीब, महिला, युवा व किसान को केंद्र में रखा। भारत ने पिछले 12 वर्षों में आस्था व आर्थिक विकास का अद्भुत संगम देखा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता मिली, जो विश्व इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मिला है। राज्य में 65 लाख गरीबों को आवास, 3 करोड़ परिवारों को शौचालय, लगभग 2 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन तथा 15 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला। कोविड काल में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। गरीब अब केवल वोट बैंक नहीं रहा, बल्कि विकास प्रक्रिया का केंद्र बन चुका है।

महिला सशक्तीकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने महिलाओं को नई पहचान दी है। उत्तर प्रदेश में भी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, बैग, पुस्तकें और स्वेटर उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटियों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का कार्य किया गया। मिशन शक्ति अभियान और पुलिस बल में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण ने महिलाओं को सुरक्षा व अवसर प्रदान किए हैं।

युवाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा, कौशल विकास,

नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को नई ऊर्जा और अवसर दिए हैं। पहली बार युवाओं को यह विश्वास मिला कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बन सकते हैं।

किसानों को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गन्ना किसानों को 3.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया के सामने सफल कोविड प्रबंधन का मॉडल प्रस्तुत किया। मुफ्त टेस्टिंग, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन और मुफ्त उपचार जैसी व्यवस्थाओं ने करोड़ों लोगों को राहत दी। इसी दौरान 'हर घर तिरंगा' अभियान के माध्यम से पूरे देश को राष्ट्रभक्ति के सूत्र में बांधा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने 'पंच प्रण' का आह्वान किया, जो विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आधारशिला हैं। इन पंच प्रणों में गुलामी की मानसिकता के अवशेषों को समाप्त करना, भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व करना, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने देश को केवल अमृत महोत्सव के उत्सव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की आस्था व सांस्कृतिक विरासत को वह सम्मान प्राप्त हुआ, जिसकी लंबे समय से अपेक्षा थी। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास, प्राण-प्रतिष्ठा तथा मंदिर पर सनातन ध्वज आरोहण जैसे तीनों ऐतिहासिक कार्य अपने कर-कमलों से संपन्न किए। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारपुरी के पुनरुद्धार जैसे कार्य भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भी कई अवसरों पर देश की आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने स्मरण कराया कि सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वहां जाने से इनकार कर दिया था और राष्ट्रपति को भी कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया था। इसके विपरीत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा और स्वदेशी व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया तथा सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। वर्षों से उपेक्षित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को संस्थागत पहचान मिली और सहकारिता क्षेत्र को विकास का नया माध्यम बनाया गया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ पहुंचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सीमा पार से होने वाले हमलों और आतंकवादी घटनाओं पर देश की प्रतिक्रिया सीमित रहती थी। यूपीए शासनकाल में दुश्मन देश भारतीय सैनिकों के सिर काटकर ले गया था, लेकिन सरकार मौन रही। संसद में इस विषय को उठाने पर संबंध खराब होने की दलील दी जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह सोच बदली और अब भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद और सीमा पार से मिलने वाली चुनौतियों का निर्णायक जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भारत की सुरक्षा व संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे उसके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई और सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की परिस्थितियों और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों को ऊर्जा संकट से बचाए रखा। जब अमेरिका सहित अनेक देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई और महंगाई ने आम लोगों को प्रभावित किया, तब भी भारत ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की तथा महंगाई को नियंत्रित रखने में सफलता प्राप्त की।

विपक्ष पर साधा निशाना, विकास व विरासत से परहेज का आरोप

मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों की राजनीति वर्षों तक भ्रष्टाचार, कुशासन, परिवारवाद, तुष्टिकरण, अव्यवस्था और असुरक्षा पर आधारित रही, उन्हें आज देश में हो रहा विकास और परिवर्तन स्वीकार नहीं हो रहा है। पहले देश की आस्था, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों से दूरी बनाई जाती थी तथा समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा और मत-मजहब के आधार पर बांटने का प्रयास किया जाता था। पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान किसान उपेक्षित रहे, उद्यमियों को हतोत्साहित किया गया, युवाओं को अवसर नहीं मिले और गरीब केवल वोटबैंक बनकर रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब विकास, सुशासन, सुरक्षा, विरासत के सम्मान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य हुआ तो वही लोग इस परिवर्तन से असहज दिखाई दे रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत की उपलब्धियों और विकास यात्रा की सराहना कर रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी दल राजनीतिक कारणों से इन उपलब्धियों को स्वीकार करने से बच रहे हैं।■

जन्म-जयंती

(फाइल फोटो)

अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल की जन्मजयंती पर विशेष

वंचित समाज को लेकर सोनेलाल का संघर्ष और स्वाभिमान जीवित रहेगा

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद की बगुलिहाई गांव में 2 जुलाई 1950 में किसान के घर पैदा हुए डॉ. सोनेलाल पटेल अपने अंतिम सांस तक गरीबों, पिछड़ों, कमेरों, दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ते रहे। वंचित समाज में अलख जगा 4 नवंबर 1995 को राजधानी लखनऊ के बेगमहजरत महल पार्क में ऐतिहासिक रैली में अपना दल की स्थापना कर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। आज की राजनीति, समाज की जिस धूरी के इर्द गिर्द घूम रही है, उस धूरी में एकजुटता का संदेश सोनेलाल ने पहले ही दे दिया था। संघर्षशील और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी सोनेलाल ने कहा था "राजनैतिक परिवर्तन के बगैर सारे परिर्वतन असंभव है, इसलिए कमेरों आगे बढ़ों और सत्ता पर कब्जा करो"। कहा था, भारत में रहने वाली समस्त जाति-बिरादरी और मजहब के लोगों को उनकी सख्या के अनुपात में शासन-प्रशासन और देश के हर हिस्से में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अपना दल का गठन करने के बाद सोनेलाल ने क्रांतिकारी और जोखिम भरा रास्ता अपनाया। वंचित समाज को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस संषर्घ के दौरान सोनेलाल को शासन- प्रशासन की दमनकारी नीतियों की यातनाएं भी झेलनी पड़ी, लेकिन अपने संकल्पों पर अडिग सोनेलाल यातनाओं से डर कर कभी पीछे नहीं हटे। 23 अगस्त 1999 में इलहाबाद के पीडी टंडन पार्क में घटी घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और इस दिन को अपना दल के कार्यकर्ता क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। सामाजिक न्याय को लेकर आवाज बुलंद करने वाले सोनेलाल ने 5 लाख लोगों के साथ अयोध्या में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसके बाद वे बोधिसत्व कहलाए। वंचित, गरीब, दलित और पिछड़े सामज के अधिकारों के लिए निरंतर जूझते रहे और चलते रहे, रुकने का नाम नहीं लिया। लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता चला गया। इसका परिणाम यह निकला कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉ. सोनेलाल पटेल की निर्णायक भूमिका दर्ज होने लगी। सामजिक न्याय के पुरोधा के रूप में डॉ. सोनेलाल पटेल की ख्याति बढ़ने लगी। सामाजिक न्याय के दायरे में जहां भी वंचित समाज के हक की बात होती, वहां सोनेलाल पहले खड़े मिलने वाले समाज के नेता के रूप में जाने गए। निरंतर वंचित समाज को लेकर चिंतनशील डॉ. सोनेलाल पटेल का 17 अक्टूबर 2009 में कानपुर में एक सड़क हादसे में असमय निधन हो गया। इस धरा-धाम पर भले ही डॉ. सोनेलाल पटेल नहीं हैं, पर वंचित समाज को लेकर उनका संघर्ष और स्वाभिमान हमेंशा जीवित रहेगा...।

अंतिम सांस तक वंचित समाज को लेकर चिंतनशील रहे पिता डॉ. सोनेलाल पटेल के संघर्ष

को अपनाकर राजनीति की पगडंडियों से बेखबर बेटी अनुप्रिया पटेल ने सफलता की कहानी गढ़ दी। पिता के निधन के बाद 28 वर्ष की आयु में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के कारवां को आगे बढ़ाने के चुनौतीपूर्ण कार्य को आत्मसात किया और पिता की राह पर चलकर अपने दम पर पिता की कर्मस्थली वाराणसी की रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से 2012 में चुनाव लड़ा और बीएसपी के उम्मीदवार को 17 हजार 583 मतों से मात देकर विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद और मजबूती से लोग जुड़ते गए और अपना दल का कारवां बढ़ता चला गया।

वर्ष 2014 में मोदी युग का प्रवेश हुआ और लोकसभा चुनाव में अपना दल का भाजपा से गठबंधन हुआ। इस गठबंधन में अपना दल के खाते में मिर्जापुर और प्रतापगढ़ की दो लोकसभा सीटें आई। मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में उतरीं और बसपा प्रत्याशी को 2 लाख 19 हजार 079 वोटों से हराकर विजय तिलक लगाया। प्रतापगढ़ से भी पार्टी प्रत्याशी कुंवर हरिवंश सिंह ने भी बसपा उम्मीदवार को चुनाव हराकर जीत दर्ज की। 5 जुलाई 2016 में अनुप्रिया पटेल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री बनीं। यहीं से शुरू हुआ अपना दल के परफॉरमेंश का 100 फीसदी का स्ट्राइक रेट, जो लगभग आज भी कायम है।

वर्ष 2016 में अनुप्रिया पटेल अपना दल (एस) की संरक्षक बनीं। वर्ष 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत पार्टी के खाते में 11 सीटें आईं; जिसमें पार्टी 9 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2018 में अपना दल (एस) के कोटे में आई सीट पर आशीष पटेल विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुने गए।

16 सितंबर 2019 में अनुप्रिया पटेल अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गईं। अपना दल कारवां बढ़ते क्रम रहा, सदन में पहुंचने का कारवां यहीं नहीं रुका। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खातें में दो सीटें आईं। एक मिर्जापुर और दूसरा राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट (सोनभद्र) की सीट रही। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल ने सपा प्रत्याशी को 2 लाख 32 हजार वोट से हराकर जीत दर्ज कीं, तो राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से पकौली लाल कोल ने सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को 54 हजार 334 वोटों से चुनाव हराया। इस बार भी पार्टी का परफॉरमेंश का 100 फीसदी का स्ट्राइक रेट रहा। 7 जुलाई 2021 में मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में फिर अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री ताज से नवाजा गया। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 12 सीटों पर शानदार जीत का रिकॉर्ड बनाया। अपना दल (एस) के लिए 4 अगस्त 2022 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की वजह से निर्वाचन आयोग ने राज्यस्तरीय पार्टी की मान्यता दे दी। इसके बाद अपना दल (एस) अब उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

(फाइल फोटो)

> **अपने संकल्पों पर अडिग डॉ. सोनेलाल शासन की यातनाओं से डर कर कभी पीछे नहीं हटे संघर्षशील और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी सोनेलाल ने कहा था "राजनैतिक परिवर्तन के बगैर सारे परिवर्तन असंभव है"**

उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी पार्टी ने इतिहास रचा। 2019 में प्रतापगढ़ सदर सीट पर हुए उपचुनाव में राज कुमार पाल ने जीत दर्ज की तो, 2023 में मिर्जापुर की छानबे सीट से रिंकी कोल ने जीत दर्ज विधानसभा पहुंचीं और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर सपा नेता आजम खां का किला फतह कर शफीक अहमद अंसारी ने शानदार जीत दर्ज।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना दल (एस) के कुल 13 विधायक हैं और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्य हैं, जो योगी कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को समझौते में दो सीटें मिली, जिसमें मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल तीसरी सांसद चुनी गईं और अभी केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। इस बार पार्टी राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से चुनाव हार गई।

राजनीति में आने के बाद अनुप्रिया पटेल सड़क से संसद तक सामाजिक न्याय की आवाज बनीं और समाज हित में उल्लेखनिय कार्य भी किए, जैसे सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी को आरक्षण का दर्जा मिला। नीट की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण मिला और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर मुखर होकर समाज हित की बात को रखा। ■

> "पिता की असामयिक निधन की वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा। जीवन भर वह वंचित कमेरा समाज, गरीब, किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। आज पिता जी साथ नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा साथ है। उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही हूं। एनडीए सरकार में पार्टी सहयोगी के तौर पर शामिल है, बावजूद सड़क से सदन तक अपने एजेंडे पर चलते हुए वंचित कमेरा समाज, किसान, गरीबों के हक और उनकी बेहतरी को लेकर उठाती रही हूं और उठाती रहूंगी"

–अनुप्रिया पटेल
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अपना दल (एस), एवं केंद्रीय मंत्री

बिहार

नीतीश युग की छाया से बाहर निकल रही 'सम्राट सरकार'

दो महीने में बदला पूरा सरकारी अमला

प्रभात कुमार

बिहार की राजनीति ने 15 अप्रैल 2026 को एक बड़ा मोड़ देखा। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद भाजपा के सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आजादी के बाद यह पहला अवसर था जब भाजपा का कोई नेता पूर्ण जनादेश के साथ बिहार की कमान संभाल रहा था। दो महीने का समय बीत चुका है। अब यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या सम्राट चौधरी वाकई नीतीश युग की लंबी छाया से बाहर निकल पाए हैं। क्या 'सम्राट मॉडल' पुरानी व्यवस्था से अलग कोई नई लकीर खींच पा रहा है। इन दो महीनों का लेखा-जोखा बताता है कि सरकार की मंशा में तेजी है, पर जमीन पर चुनौतियां उससे कहीं अधिक गहरी और जटिल हैं।

सरकार ने सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का उठाया। शपथ के 60 दिन के भीतर गृह, वित्त, पथ निर्माण और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रधान सचिव बदल दिए गए। लगभग 18 जिलों के जिलाधिकारी और 22 जिलों के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में नीतीश युग के भरोसेमंद माने जाने वाले अधिकारियों की जगह नए चेहरों को लाया गया। संदेश साफ था कि पुरानी टीम के साथ नई पारी नहीं खेली जाएगी। अधिकारियों को यह भी दो-टूक बता दिया गया कि अब 'परफॉर्म करो या बाहर जाओ' की नीति चलेगी। सचिवालय में फाइलों की रफ्तार बढ़ी है, यह दिखता है पर समीक्षा यह कहती है कि तबादला करना सबसे आसान काम है, डिलीवरी कराना सबसे मुश्किल।

नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी हर छह महीने पर बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले होते थे, लेकिन जमीन पर योजनाओं के क्रियान्वयन की गति वैसी नहीं बढ़ी। सम्राट सरकार ने पटना मेट्रो, जेपी गंगा पथ के विस्तार और उत्तर कोयल नहर जैसी परियोजनाओं को डेडलाइन दी है। पर ये सभी योजनाएं नीतीश सरकार के समय की हैं। नया विजन क्या है, बिहार को अगले पांच साल में कहां ले जाना है, इसका कोई ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया है।

कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सम्राट चौधरी ने गृह विभाग अपने पास रखा है। पहली ही समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि थाना बिकेगा नहीं और अपराधी टिकेगा नहीं। हर शनिवार को थाना दिवस मनाने का आदेश दिया गया है। इस दिन जिले के पुलिस अधीक्षक को खुद थाने में बैठकर जनता की शिकायत सुननी है। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया पर एसटीएफ की कार्रवाई तेज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि एक महीने में 1200 से अधिक बालू लदे ट्रक जब्त किए गए और 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। यह पहल अच्छी है, पर बिहार पुलिस की समस्या सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति की नहीं है। थानों में स्वीकृत बल की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। 2015 के बाद कोई बड़ी बहाली नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरे लगाने का टेंडर निकाल दिया गया है, पर उनके मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का सिस्टम कौन देखेगा, यह साफ नहीं है। बालू और शराब पर कार्रवाई हर नई सरकार के शुरुआती दिनों में होती है, पर कुछ महीनों बाद ढीली पड़ जाती है।

असली परीक्षा मानसून के बाद आएगी जब नदियों में फिर से बालू का खनन शुरू होगा। शराबबंदी को लेकर सरकार ने समीक्षा समिति बना दी है। यह नीतीश कुमार से अलग रुख है। पर समिति का गठन शराबबंदी हटाने के लिए हुआ है या सिर्फ कानून को व्यावहारिक बनाने के लिए, इस पर सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। दुविधा यहां भी बनी हुई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को खुली छूट देने का दावा किया है। निबंधन, राजस्व और परिवहन विभाग के दफ्तरों में औचक छापे पड़ रहे हैं। चर्चा है कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में नियुक्त दो पूर्व मंत्री और कई शीर्ष अधिकारी जांच के दायरे में हैं। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि नया शासन आएगा तो नई जवाबदेही भी आएगी। पर समीक्षा यह मांग करती है कि यह कार्रवाई चयनात्मक न लगे। अगर सिर्फ नीतीश युग के अधिकारियों और नेताओं को निशाना बनाया गया और भाजपा कोटे के दागी लोग बच गए तो पूरा अभियान अपनी

विश्वसनीयता खो देगा। अनिल सहनी जैसे मामले भाजपा भी झेल चुकी है। इसलिए जीरो टॉलरेंस की नीति तभी मानी जाएगी जब कार्रवाई पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हो। अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। छापों की खबरें अखबारों में हैं, पर चार्जशीट कोर्ट में नहीं पहुंची है। दो महीने में पूरा सिस्टम तो नहीं बदलता, पर सरकार की नीयत जरूर दिख जाती है। अभी तक नीयत 'दिखाने' पर ज्यादा है, 'करने' पर कम।

सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी और सबसे विकट चुनौती राज्य का खाली खजाना है। बिहार का राजकोषीय घाटा साढ़े तीन प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने के बाद विकास योजनाओं के लिए पैसा ही नहीं बचता। सात निश्चय, हर घर नल का जल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी पुरानी योजनाओं की देनदारी हजारों करोड़ रुपये में है। मुख्यमंत्री की नजर लगातार केंद्र सरकार पर टिकी है। दो महीने में वे दो बार दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से मिल चुके हैं। उनकी मांग तीन सूत्री है। पहला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया जाए। तीसरा, केंद्रीय करों में राज्य की लंबित हिस्सेदारी तुरंत दी जाए। भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार होने का फायदा बिहार को मिलेगा। पर 2015 से 2020 के बीच भी डबल इंजन की सरकार थी, तब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समीक्षा यह कहती है कि केंद्र पर पूरी तरह निर्भर रहना स्थायी समाधान नहीं है। बिहार का अपना राजस्व संग्रह, खासकर जीएसटी, देश में सबसे कम है। शराबबंदी के कारण राज्य को हर साल पांच हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अगर समीक्षा समिति शराबबंदी हटाने की सिफारिश करती है तो राजस्व बढ़ेगा, पर यह नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विरासत से टकराव होगा। अगर शराबबंदी जारी रखी तो खजाना खाली ही रहेगा। सम्राट सरकार इस दोराहे पर खड़ी है और अभी तक उसने यह नहीं बताया कि बिहार अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा।

निवेश और रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने 25 अप्रैल को नई निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की। इसके तहत 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वालों को पांच साल तक बिजली बिल में पचास प्रतिशत की छूट मिलेगी। बियाडा की खाली पड़ी 2800 एकड़ जमीन को ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया गया है। स्टार्टअप बिहार 2.0 योजना शुरू की गई है जिसके तहत युवाओं को बिना गारंटी दस लाख रुपये तक का लोन देने का वादा है। कागज पर ये नीतियां आकर्षक लगती हैं। पर बिहार में निवेश का पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। नीतीश कुमार के समय में भी सिंगल विंडो सिस्टम बना, पर जमीन विवाद, बिजली की कमी और कानून-व्यवस्था के कारण बड़े उद्योग नहीं आए। सम्राट सरकार को सिर्फ नीति नहीं, भरोसेमंद माहौल देना होगा। उद्यमी को यह भरोसा चाहिए कि उसकी फैक्ट्री तक जाने वाली सड़क पर बालू माफिया का कब्जा नहीं होगा और स्थानीय नेता हर महीने रंगदारी नहीं मांगेगा। दो महीने में 1200 से अधिक युवाओं ने स्टार्टअप के लिए आवेदन किया है, पर कितनों को लोन मिला और कितनों का स्टार्टअप शुरू हुआ, इसका कोई आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है। 1.2 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है। यह कदम जरूरी था, पर भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी यह कोई नहीं जानता। बीपीएससी और एसएससी का कैलेंडर सालों से लटकता रहा है। बिहार में बेरोजगारी की दर 15 प्रतिशत से ऊपर है। युवाओं को तुरंत रोजगार चाहिए, नई नीति का इंतजार नहीं कर सकते।

राजनीतिक रूप से सम्राट चौधरी यह संदेश देना चाहते हैं कि वे नीतीश कुमार की फोटो कॉपी नहीं हैं। उनके फैसले भी यही दिखाते हैं। नीतीश कुमार सात निश्चय के मॉडल पर चले थे। सम्राट चौधरी निवेश और रोजगार की बात कर रहे हैं। नीतीश ने शराबबंदी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। सम्राट ने उस पर समीक्षा समिति बैठा दी। नीतीश ने अफसरशाही पर भरोसा किया। सम्राट ने आते ही अफसरशाही को बदल दिया। पर नीतीश कुमार की छाया से पूरी तरह निकलना आसान नहीं है। भाजपा के पास अपना कोई स्वतंत्र बिहार मॉडल नहीं है। 18 साल तक नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहने के कारण पार्टी की अपनी अलग पहचान दब गई थी। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे एंटी-नीतीश दिखें, पर एंटी-विकास न लगें। क्योंकि ग्रामीण बिहार में आज भी अच्छी सड़क, बिजली और लड़कियों की साइकिल योजना के लिए नीतीश कुमार को याद किया जाता है। दूसरी राजनीतिक चुनौती सामाजिक समीकरण की है। नीतीश कुमार ने कुर्मी-कोइरी, अति पिछड़ा, महादलित और पसमांदा मुस्लिम का एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ बनाया था। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा यानी कोइरी समाज से आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने से लव-कुश समीकरण का एक हिस्सा सधेगा, पर कुर्मी वोट, अति पिछड़ा वोट और मुस्लिम वोट का क्या होगा। भाजपा का पारंपरिक कोर वोटर अगड़ी जातियां और वैश्य समाज माना जाता है। अगर सम्राट चौधरी सिर्फ एक जाति के नेता बनकर रह गए तो 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

निष्कर्ष यह है कि दो महीने में सम्राट सरकार ने तेजी जरूर दिखाई है। तबादले किए, छापे मरवाए, नई नीतियां बनाईं। आम जनता को लगा कि कुछ नया हो रहा है। इसे राजनीति की भाषा में हनीमून पीरियड कहते हैं। हर नई सरकार के शुरुआती दिन ऐसे ही उत्साह से भरे होते हैं। पर असली परीक्षा अब शुरू होगी। कुछ ही दिनों में मानसून आने वाला है। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। तटबंधों की मरम्मत का काम अभी अधूरा है। अगर बाढ़ प्रबंधन में सरकार फेल हुई तो बनती हुई छवि बिगड़ते देर नहीं लगेगी। खजाना खाली पड़ा है। अगर केंद्र सरकार ने तुरंत पैसा नहीं दिया तो कर्मचारियों को वेतन देने में भी मुश्किल आएगी। निवेश के प्रस्ताव कागज से निकलकर जमीन पर नहीं उतरे तो बेरोजगार युवा फिर से सड़कों पर आ जाएगा।

सम्राट चौधरी के पास नीतीश कुमार की तरह 18 साल का लंबा समय नहीं है। 2025 के अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। यानी उनके पास काम करके दिखाने के लिए सिर्फ 14 महीने हैं। इन 14 महीनों में उन्हें साबित करना है कि वे केवल प्रशासनिक फेरबदल करने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि जनता के नेता भी हैं।

नीतीश कुमार की छाया से बाहर निकलने के लिए सिर्फ अधिकारियों का चेहरा बदलना काफी नहीं है। नीति बदलनी पड़ेगी, नीयत साफ दिखानी पड़ेगी और जमीन पर नतीजा देना पड़ेगा। अभी तक सम्राट सरकार ने अपना इरादा जाहिर किया है। इलाज अभी बाकी है। पूरा बिहार देख रहा है कि सम्राट मॉडल पुरानी बीमारियों की दवा बनता है या खुद एक नई बीमारी बनकर सामने आता है।■

नौकरी नहीं, भरोसे की जिम्मेदारी मिली है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नवचयनित कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र
कहा-आपकी सैलरी आम जनता देती है इसे ध्यान में रखकर काम करें

कौस्तुभ कुमार मलयज

झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी कतारें, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और दूर-दराज के इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की चुनौतियों को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नव-चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है और इसके लिए आने वाले दिनों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ खाली पद भरना नहीं है। असली लक्ष्य यह है कि गांव हो या शहर, हर मरीज को समय पर इलाज मिले और उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े।

मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त अधिकारियों से कहा कि नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अस्पताल में आने वाला हर मरीज इस उम्मीद से आता है कि उसे राहत मिलेगी। ऐसे में आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार और आपकी संवेदनशीलता ही सरकार की पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने वाला कर्मचारी सिर्फ अपना दायित्व नहीं निभाता, बल्कि पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी मजबूत करता है। हेमंत सोरेन ने माना कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में अभी भी विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित मानवबल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार इस कमी को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी बड़े स्तर पर बहालियां होंगी। उन्होंने कहा कि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी विकसित राज्य की पहचान होती है। सरकार चाहती है कि झारखंड का हर सरकारी अस्पताल संसाधनों और मानवबल के मामले में पहले से ज्यादा सक्षम बने।

सीएम ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर ने पूरी दुनिया को सिखाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है। उस समय डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रशासन ने जिस तरह काम किया, उसने यह भी बताया कि मजबूत व्यवस्था के बिना किसी भी संकट से लड़ना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि भविष्य

में ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और प्रशिक्षित मानवबल पर लगातार निवेश कर रही है।

सीएम ने कहा कि विकास केवल सड़क, पुल या भवन बनाने से नहीं होता। जब लोगों को अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज और रोजगार मिलता है, तभी विकास का वास्तविक लाभ समाज तक पहुंचता है। इसी सोच के साथ सरकार अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों को भरने का काम लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानवबल के बिना कोई भी सरकारी व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम नहीं कर सकती। इसलिए बहाली की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, 151 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर समेत कुल 262 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। सरकार ने इसे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, डॉक्टरों की कमी दूर करने और अस्पताल प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की भूमिका जितनी बड़ी है, अस्पतालों के सफल संचालन में मैनेजमेंट और प्रशासनिक कर्मियों की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। आपकी नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि आम जनता को किसी तरह की दिक्कत न हो, आप अब सरकार के अभिन्न अंग हैं। आपकी सैलरी आम जनता देती है, इसलिए उसी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। उन्होंने डॉक्टरों को भगवान का रूप बताते हुए कहा कि उसी भावना के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए।

हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर नव नियुक्त कर्मियों को देश के बड़े संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, ताकि वहां की कार्यप्रणाली सीखकर झारखंड में बेहतर व्यवस्था विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार नई चुनौतियां आती हैं और उनका मुकाबला जिम्मेदारी के साथ करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक समय झारखंड में डॉक्टरों पर इलाज के साथ-साथ कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी थीं, लेकिन अब सरकार व्यवस्था को व्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने बजट का बड़ा हिस्सा वेतन मद में खर्च कर रही है, इसलिए सभी कर्मियों को आम जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना दिशोम गुरु शिबू सोरेन का सपना था और हेमंत सरकार उसी सपने को धरातल पर उतारने में जुटी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट लक्ष्य राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना है और सरकार उसी दिशा में लगातार काम कर रही है।

इरफान अंसारी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार तेजी से बैकलॉग दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के डॉक्टर अक्सर बेहतर संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें झारखंड में ही बेहतर माहौल और अवसर देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता राज्य के अंतिम छोर तक सुनिश्चित हो और हर पंचायत तक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैंने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली है, बल्कि जनता की सुविधाओं की पहरेदारी की जिम्मेदारी ली है, जो दर्द समझता है, वही इलाज करता है।

उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में राज्य के नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 तक की गई है। साथ ही झारखंड में मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में और नियुक्तियां की जाएंगी।

इस मौके पर अवर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में अभी तक खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की संख्या सिर्फ 20 थी, जो नई नियुक्तियों के बाद बढ़कर 76 हो जाएगी। उन्होंने नव नियुक्त खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों से पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ काम करने की अपील की, ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों से कहा कि जहां भी उनकी पोस्टिंग हो, वहां आईपीएचएस मानकों के अनुरूप इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में की गई है, जिससे डॉक्टरों की कमी काफी हद तक दूर होगी और लोगों को अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। अजय कुमार सिंह ने कहा कि अस्पतालों में फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने डॉक्टरों से अनावश्यक रेफर की प्रवृत्ति कम करने और अधिक से अधिक मरीजों का इलाज अपने अस्पताल में ही करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि नव नियुक्त डॉक्टरों को वेतन के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ताकि वे बेहतर मनोयोग से सेवा दे सकें। उन्होंने सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजरों से भी अस्पताल प्रबंधन, संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।■

पहाड़ पर हौसलों की जीत

जब देश की सबसे बड़ी जोजिला सुरंग ने पार किया महत्वपूर्ण पड़ाव

पंचायत वॉयस, जम्मू-कश्मीर

जब देश की सबसे बड़ी जोजिला सुरंग ने पार किया महत्वपूर्ण पड़ाव तो लद्दाख का सर्दियों का 'वनवास' समाप्त होने की उम्मीद जाग गई, जो कि पहाड़ पर हौसलों की जीत से कम नहीं है। अब आने वाले दिनों में सुरंग के बन जाने पर महज 11 घंटे में श्रीनगर से नई दिल्ली सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकेगा। यह देश के लिए भी एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि से कम नहीं है। दरअसल, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी जोजिला सड़क सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर हिमालय को काटकर बनाई जा रही है। यह 13.153 किलोमीटर लंबी है जो कि 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची है। श्रीनगर-लेह हाईवे पर बनाई जा रही सिंगल ट्यूब व द्वि-दिशीय सड़क सुरंग के निर्माण पर करीब 6,800 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना जताई जा रही है। इस सुरंग का निर्माण अगले डेढ़ वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस परियोजना का शुभारंभ मई, 2018 में किया था। 2020 में इस परियोजना के निमार्ण की जिम्मेदारी मेघा

जोजिला टनल के एक हिस्से को विस्फोट कर तोड़े जाने के मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व मुख्यमंत्री उमर अब्दुला

पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी सुरंग

जोजिला सुरंग रणनीतिक रूप से ही न सिर्फ बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सुरंग पर्यटकों के आकर्षण का भी मुख्य केंद्र होगा। वर्ष भर पर्यटक लद्दाख जाते रहेंगे, जिससे लद्दाख के आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।

इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सौपी गई थी। कंपनी ने न्यू आस्ट्रियन टनलिंग मेथड तकनीक से काम किया। यह सोनमर्ग से लगभग 24 किलोमीटर और श्रीनगर से 103 किलोमीटर दूर स्थित है। यह सुरंग कश्मीर के गांदरबल के बालटाल को लद्दाख के द्रास जिले के मीनामर्ग से जोड़ेगी। परियोजना में 18 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क भी शामिल है।

गत दिनों परियोजना के अंतिम 2.5 मीटर हिस्से को विस्फोट के जरिए तोड़ा गया, जिसे जून के शुरुआती सप्ताह में ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लद्दाख के मीनामर्ग में ईस्ट पोर्टल के निकट रिमोट बटन दबाकर सुरंग में विस्फोट किया था। इसके साथ ही पूरा देश खुशी से झूम उठा था, क्योंकि जोजिला सुरंग के आरपार होना पहाड़ पर हौसलों की जीत से कम नहीं है। यातायात के लिए सुरंग खुलने के बाद दुश्मन के पास लद्दाख में सर्दियों में दुस्साहस करने पर कोई रणनीति या सामरिक लाभ नहीं मिलेगा। जोजिला सुरंग दुश्मन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि हमारी सेना के आगे बढ़ने में अब कोई बाधा नहीं है। देश की सेना लद्दाख में पूरा साल अपनी रणनीतिक तैयारियों को तेजी देगी। आने वाले पांच सालों में और भी कई सुरंग तैयार होकर देश को रणनीति रूप से मजबूत करेंगी।

यह परियोजना लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए जीवन रेखा भी है। इसी कारण श्रमिकों ने माइनस चार डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर अपना योगदान दिया है, क्योंकि यह परियोजना लद्दाख क्षेत्र के लोगों को श्रीनगर से हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। बता दें कि लद्दाख में सर्दियों का मौसम सबके लिए चुनौतियां लेकर आता है। सर्दियों में जोजिला (दर्रा) पर बर्फ की एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो कश्मीर की ओर से वाहनों को बालटाल तक ही सीमित कर देती थी। वर्ष 2019 से पहले लद्दाख करीब पांच महीने तक शेष देश से सड़क मार्ग से कटा रहता था। इसके बाद सीमा सड़क संगठन के हिमवीरों की बदौलत कड़ी मेहनत से जोजिला को अधिक से अधिक देर तक खुला रखने का अभियान शुरू किया गया, जो अब जल्द जोजिला सुरंग बन जाने से काफी राहत मिलेगी। सर्दियों में भारी हिमपात के कारण महीनों बंद रहता है लेह-श्रीनगर हाईवे पर जोजिला पास, लेकिन परियोजना के पूरी हो जाने के बाद मात्र 15 मिनट में ही तीन घंटे का सफर पूरा हो जाएगा। बहरहाल, वर्ष 2020 में चीनी सेना से हिंसक संघर्ष के बाद क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं की रणनीतिक तैयारियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में काफी काम हुआ है। पिछले पांच सालों में लद्दाख में सैनिकों, अति आधुनिक टैंकों, बड़ी तोपों, ड्रोन, संचार यंत्रों की संख्या में भारी वृद्धि करने के साथ दुश्मन को घेरने के लिए क्लास 70 पुलों व सड़कों का जाल फैलाया गया है।■

निर्माण कार्य में कई चुनौतियां आईं

- पिछले पांच वर्षों में निर्माण स्थल पर पांच बड़े हिमस्खलन हुए, जिनमें जनवरी 2023 की घटना सबसे गंभीर थी। इसके बावजूद परियोजना ने एक करोड़ सुरक्षित मानव-कार्य घंटे का रिकार्ड बनाया है।
- इंजीनियरों, कर्मचारियों व श्रमिकों को कड़ाके की ठंड व कम आक्सीजन में काम करना पड़ा।
- सुरंग के कुछ हिस्सों में कमजोर चट्टानों के कारण कार्य की गति प्रभावित भी हुई।

सुरंग में होंगी यह सुविधाएं :

सुरंग में अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, स्वचालित अग्नि पहचान प्रणाली, आधुनिक सीसीटीवी निगरानी और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्रास-पैसेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा परियोजना में आठ कट-एंड-कवर सेक्शन, चार पुल, 40 कल्वर्ट, स्नो गैलरी, कैच डैम, हिमस्खलन सुरक्षा संरचनाएं और आधुनिक पहुंच मार्ग भी शामिल हैं।

महराजगंज

परिवर्तन की नई कहानी गढ़ रहा जागृति

अब दिल्ली-मुंबई नहीं, स्वरोजगार को सम्मानजनक विकल्प के रूप में देख रहे युवा

P अमर हिंदुस्तानी

कभी महराजगंज के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का मतलब अक्सर गांव छोड़ना होता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई का रास्ता पकड़ना आम बात थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां एक बदलाव दिख रहा है। युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाने की बजाय अपने ही क्षेत्र में अवसर तलाश रहे हैं। कोई कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा है, कोई स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यवसाय शुरू कर रहा है और कोई गांव में ही रहकर नई तकनीक के साथ काम कर रहा है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अब उद्यम शुरू करने वाले लोगों को पहले की तुलना में अधिक मार्गदर्शन और सहयोग मिलने लगा है। इसमें सार्थक सहयोगी की भूमिका निभा रहा है जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल (JECP) का महाराजगंज उपकेंद्र।

अक्टूबर 2024 में स्थापित जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल के महाराजगंज उपकेंद्र ने स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू किया। वर्तमान में इससे जुड़ युवा कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद, सेवा क्षेत्र और छोटे विनिर्माण इकाइयों में नए प्रयोग कर रहे हैं। उपकेंद्र का प्रयास केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमियों को बाज़ार, विशेषज्ञों और वित्तीय अवसरों से जोड़ना भी है। जिले के कई उद्यमियों की चुनौतियां एक जैसी हैं - पूंजी की कमी, पैकेजिंग और ब्रांडिंग का अभाव, बाज़ार तक सीमित पहुंच तथा व्यवसाय प्रबंधन की जानकारी का अभाव। ऐसे में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मार्गदर्शन और नेटवर्किंग उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। यही कारण है कि अब स्वरोजगार को भी सम्मानजनक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है।

बाघापार गाँव के रामलगन उपाध्याय इसका उदाहरण हैं। पास्ता और मैकरोनी निर्माण से जुड़े उनके उद्यम को गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और निवेश से जुड़ाव का लाभ मिला। वहीं युवा उद्यमियों का एक नया समूह कृषि आधृत मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। संख्या भले अभी सीमित हो, लेकिन संकेत बताते हैं कि जिले में उद्यमिता की नई संस्कृति आकार ले रही है।

क्या है जागृति?

जागृति की शुरुआत 2008 में "जागृति यात्रा" से हुई। यह देशभर के युवाओं को उद्यमिता, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देने वाली वार्षिक रेल यात्रा है।

"पहले हम केवल उत्पादन पर ध्यान देते थे। अब गुणवत्ता, पैकेजिंग और बाज़ार की समझ बढ़ी है। इससे व्यवसाय को विस्तार देने का आत्मविश्वास मिला है।"

- रामलगन उपाध्याय, को-फाउंडर, रेणुका लघु उद्योग

"जागृति उद्यम केंद्र के इन्क्यूबेशन कार्यक्रम से जुड़ने के बाद कॉस्टिंग और प्राइसिंग की जानकारी ने मेरे व्यवसाय को नई दिशा दी है। अब मैं अपने निर्णय अधिक आत्मविश्वास और आँकड़ों के आधार पर ले पा रहा हूँ, जिससे व्यवसाय की लाभप्रदता में सुधार हो रहा है।"

- अनुभव मिश्रा, फाउंडर, अनुभव टेक्सटाइल्स

"पूर्वांचल में प्रतिभा और मेहनत की कमी नहीं है। जरूरत ऐसे माहौल की है जहाँ लोग अवसरों को पहचान सकें और अपने ही क्षेत्र में उद्यम खड़ा करने का आत्मविश्वास विकसित कर सकें। जागृति पूर्वांचल में ऐसे ही ईकोसिस्टम का निर्माण कर रही है।"

- आशुतोष कुमार, सीईओ, जागृति

पिछले डेढ़ दशक में 9000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। इसी अनुभव के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागृति के केंद्र स्थापित किए गए। देवरिया जिले के बरपार में स्थित जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात जिलों में उद्यमिता आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। यहाँ इन्क्यूबेशन, मेंटरशिप, बाज़ार संपर्क, वित्तीय अवसर और उद्यमिता प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। संस्था का मानना है कि छोटे जिलों की स्थानीय प्रतिभाएँ ही क्षेत्रीय विकास की सबसे बड़ी ताकत हैं।

7M मॉडल

उद्यम कोर शाहज़ेब अली बताते हैं कि जागृति की कार्यप्रणाली 7M मॉडल पर आधारित है। इसमें मोबिलाइजेशन के माध्यम से संभावित उद्यमियों की पहचान की जाती है। मेंटरशिप के तहत विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलता है। मार्केट के जरिए बाज़ार से जुड़ाव, मनी के माध्यम से वित्तीय अवसरों तक पहुँच और मित्र के जरिए सहयोगी नेटवर्क विकसित किया जाता है। माहौल उद्यमिता के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है, जबकि अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों को व्यवसाय की विभिन्न प्रक्रियाओं में सहयोग दिया जाता है। यह मॉडल विचार से लेकर व्यवसाय विस्तार तक की पूरी यात्रा में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

महराजगंज की चुनौतियाँ

सीमावर्ती जिला होने के कारण महराजगंज में उद्यमिता की संभावनाएँ तो हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। अधिकांश उद्यमियों के सामने पूँजी जुटाने की समस्या रहती है। स्थानीय स्तर पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जानकारी सीमित है। डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स का उपयोग अभी शुरुआती स्तर पर है। कई उद्यमियों को लाइसेंस, पंजीकरण और सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी भी नहीं होती। यही कारण है कि अच्छे उत्पाद होने के बावजूद वे बड़े बाज़ार तक नहीं पहुँच पाते। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन बाधाओं को कम किया जाए तो कृषि आधारित उद्यमों के लिए जिले में बड़ी संभावनाएँ मौजूद हैं।

आगे की दिशा

महाराजगंज उपकेंद्र आने वाले वर्षों में महिला और युवा उद्यमिता पर विशेष ध्यान देना चाहता है। कृषि आधृत मूल्य संवर्धन इकाइयों, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और डिजिटल बाजार तक पहुँच को प्राथमिकता दी जा रही है। लक्ष्य केवल नए उद्यम शुरू कराना नहीं, बल्कि ऐसे व्यवसाय विकसित करना है जो स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा करें। इसके साथ उद्यमियों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने पर भी काम किया जा रहा है, ताकि वे अनुभव, बाज़ार और अवसरों को साझा कर सकें। ■

बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा जम्मू-कश्मीर

उपराज्यपाल ने बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में की बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा

P राज लक्ष्मी

इन दिनों पूरा जम्मू-कश्मीर बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है, क्योंकि जुलाई माह के पहले सप्ताह से ही बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। देश-विदेश से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्त भी दर्शन को बेकरार नजर आ रहे हैं। इस वर्ष साढ़े तीन लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है। तीन जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार की सुबह बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा अर्चना करके कर दी। बाबा अमरनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ करते हुए उपराज्यपाल ने बाबा बर्फानी से देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने देशभर के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए

आने का आह्वान किया। कहा कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के सफल संचालन के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय समुदाय, सेवा प्रदाता और स्वयंसेवक पूरी समन्वय भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। सभी का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और यादगार यात्रा अनुभव प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष यात्रा मार्गों पर आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों के सहयोग से प्रशासन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदीप कुमार भंडारी, कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग, कश्मीर के आइजी पुलिस वीके बिरदी सहित प्रशासन और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्राइन बोर्ड की ओर से प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में प्रथम पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 57 दिवसीय बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को

पवित्र गुफा में प्रथम पूजा के दौरान न्यास सदस्य अनिल सूरी ने अपनी भावना व्यक्त की, कहा कि इस बार हिमलिंग का आकार काफी छोटा नज़र आ रहा है।

आपरेशन शिवा के माध्यम से गुफा तक पहुंचा रही सेना

देश-विदेश से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों को आतंकी खतरे से सुरक्षित रखने के लिए सेना आपरेशन शिवा के माध्यम से गुफा तक पहुंचा रही है। तीर्थयात्रा के सुरक्षा कवच को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए सेना ने यात्रा मार्ग और साथ सटे उन इलाकों में ड्रोन खतरों से निपटने के लिए ड्रोन रोधक प्रणालियां और इलेक्ट्रानिक युद्धक उपकरणों से युक्त समर्पित मानवरहित हवाई प्रणाली तैनात की है। इसके अलावा चिह्नित स्थानों पर फेस रिक्गिनशन प्रणाली से लैस अत्याधुनिक कैमरे भी लगाए हैं। सभी आधार शिविरों और यात्रा मार्ग पर चिह्नित स्थानों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। सेना ने यात्रा मार्ग पर क्यूआरटी और क्यूएटी दस्तों के अलावा अपने बम निरोधक दस्ते डाग स्क्वाड और माउंटेन रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया है। इतना ही नहीं, सेना ने यात्रा मार्ग और उसके आसपास की पहाड़ियों पर मोर्चा भी संभाल रखा है, ताकि कोई आतंकी अगर छिपा है तो उसे वहीं मार गिराया जा सके। सेना ने अपनी निगरानी चौकियां और वाचटावर भी स्थापित किए हैं। अपने हेलीकाप्टर भी विशेष परिस्थितियों के लिए तैनात कर रखे हैं। सेना की चिनार कोर के अधीनस्थल किलो फोर्स और विक्टर फोर्स इस यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बल की 670 कंपनियों की तैनाती कर रखी है।

रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग दोनों रास्तों से एक साथ संचालित की जाएगी।

जम्मू आधार शिविर भगवती नगर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धा व आस्था के साथ बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया। इसके साथ ही पूरा जम्मू कश्मीर बम-बम भोले व भारत माता की जय के जयघोष के साथ गूंज उठा। कहीं डमरू की ध्वनि तो, कहीं शंखनाद सुनाई दे रहा है। सभी भक्त जम्मू से रवाना होने के बाद दो मार्ग से बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचते हैं, जिनमें एक मार्ग अनंतनाग जिले से होकर शामिल है। यह पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान-पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबा छोटा, लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाले बाल्टल मार्ग से होकर जानी पड़ती है। जम्मू से जेकेआरसीटीसी के बस से रवाना हुए जत्थे का जगह-जगह स्वागत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी पहुंचे श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखते ही बन रहा है।

श्रद्धालुओं का कहना है कि जैसे-जैसे बाबा के नजदीक पहुंच रहे हैं तो खुशी भी बढ़ती जा रही है। समुद्रतल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रीअमरनाथ जी की इस पवित्र गुफा की यात्रा का सिर्फ भगवान शंकर के मतवालों को ही नहीं, बल्कि कश्मीर के एक बड़े वर्ग को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। ये यात्रा मुस्लिम परिवारों को रोजगार देने का काम करती है। यही वजह है कि घाटी पहुंचने पर मुस्लिम समाज भी यात्रियों का भव्य स्वागत कर रहा है। जम्मू-कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और होटलियर्स क्लब जैसी प्रमुख टूरिज़्म संस्थाएं अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए होटलों व टैक्सी किराये में 50 से 65 प्रतिशत तक की छूट दे रही है। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार इस कदम का मकसद तीर्थयात्रा को सस्ता बनाना और घाटी की यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों का भरोसा फिर से कायम करना है। बहरहाल, जत्थे के रवाना होते समय श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था, क्योंकि कोई हाथ में त्रिशूल लिए भगवान शिव की वेशभूषा में था, तो कोई जयघोष में मग्न दिखा। इन सबके बीच

प्रशासन का कहना है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान अमरेश्वर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त जम्मू रेलवे स्टेशन का नया भवन और सात नए प्लेटफार्म भी अमरनाथ यात्रियों का स्वागत कर रहा है। ऑपरेशन 'हॉक आई' से अमरनाथ यात्रा की अभेद्य सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। आसमान में ड्रोन, जमीन पर स्नाइपर और 416 सीसीटीवी कैमरों का पहरा, यात्रा मार्ग पर चौबीसों घंटे निगरानी होगी।

500 करोड़ का बूस्टर डोज : एक ओर जहां लाखों सनातन प्रेमियों के लिए यह यात्रा आस्था की केंद्र है, वहीं हजारों कश्मीरियों और पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए यह आजीविका का प्रमुख साधन भी है। एक माह पूर्व ही गांवों से घोड़े वाले, पौनी वाले यात्रा के पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। टेंट लगाने से लेकर प्रसाद व बरसाती बेचने वाले, टैक्सी से लेकर होटल संचालकों और उसमें कार्य कर रहे हजारों कामगारों के लिए यह यात्रा वर्ष भर में एक अवसर से कम नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है तो यह यात्रा नई उम्मीद देती है, क्योंकि 50 हजार से ज्यादा स्थानीय लोग सीधे इस यात्रा से जुड़ जाते हैं। इसी कारण सभी बेसब्री से इंतजार रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस यात्रा से पांच-छह माह का खर्च निकल जाता है।

श्रीअमरनाथ यात्रा के दोनों आधार शिविरों, पहलगाम व बालटाल से पवित्र गुफा तक करीब पांच-पांच हजार घोड़े वाले पंजीकृत हैं। इसके अलावा पिट्ठू और पालकी वाले भी करीब पांच-पांच हजार स्थानीय लोग हैं। चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा तक एक तरफा 4,810 रुपये घोड़े के निर्धारित हैं। दो माह की यात्रा में करीब 20 हजार घोड़ा-पिट्ठू व पालकी वाले एक-एक लाख रुपये तक कमा लेते हैं। यानी यह यात्रा इन लोगों को करीब 200 करोड़ की नई ऊर्जा देती है। इसी तरह यात्रा मार्ग पर करीब दो हजार टेंट स्थानीय लोगों की ओर से लगाए गए हैं। जगह व सुविधा के अनुसार, किराया भी निर्धारित है। 550 से लेकर 850 रुपये प्रति दिन के लिए जाते हैं। इसके अलावा नुनवान से चंदनवाड़ी तक स्थानीय लोग ही श्रद्धालुओं को टैक्सी की सेवा मुहैया करवाते हैं। यात्रा मार्ग पर छोटे दुकानदार, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर चलने वाले टैक्सी चालक, जम्मू व कश्मीर में होटल वाले व पर्यटन स्थलों पर काम करने वालों को मिलाकर यह यात्रा करीब 50 हजार लोगों के लिए 500 करोड़ से अधिक की आर्थिकी लाती है। आसान तरीके से समझें तो अगर चार लाख यात्रा रहती है और प्रति श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान औसतन 13,000 रुपये भी खर्च करता है तो आंकड़ा 500 करोड़ से अधिक हो जाता है।■

भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी अमरत्व की कथा

कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर-पूर्व में स्थित श्रीअमरनाथ जी हिन्दुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। श्रीअमरेश्वर धाम दक्षिण कश्मीर में समुद्रतल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरेश्वर धाम में ही भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी और इसे श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा भी कहते हैं। अमरनाथ की गुफा की प्रमुख विशेषता यह है कि यहां पर बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग प्रत्येक वर्ष बनता है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। गुफा की परिधि लगभग डेढ़ सौ फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह-जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक स्थान पर इन टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग दस फुट ऊंचा शिवलिंग बनता है। चन्द्रमा के घटने-बढ़ने के साथ-साथ इस बर्फ का आकार भी घटता-बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे-धीरे छोटा होता जाता है। इस वर्ष श्री अमरेश्वर धाम की तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू हो गई है। यह तीर्थयात्रा 1989 से लगातार पाकिस्तान समर्थक आतंकियों के निशाने पर रही है। कई बार तीर्थयात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है।

बाबा बर्फानी की यात्रा में न पालीथीन, न थर्माकोल

- बालटाल, पहलगाम आधार शिविरों में दिए जाएंगे यात्रियों को कपड़े के थैले
- दोनों यात्रा मार्गों पर 15 स्थानों पर होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था
- चार हजार कर्मी सफाई और 623 कर्मी संभालेंगे कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी
- इस वर्ष पंद्रह प्रतिशत कचरा कम करने का लक्ष्य, गत वर्ष इकट्ठा हुआ था 450 टन कचरा
- इंदौर का गैर सरकारी संगठन स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट संभाल रहा कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी

ग़ज़ल

P डॉ. अंजना सिंह सेंगर

सींचिये पौधों को तो फूल औ फल देते हैं
वक़्त लगता है मगर कुछ तो बदल देते हैं।
ऐसे लोगों की तरक़्क़ी नहीं रुकती है कभी
वक़्त के प्रश्नों का दो टूक जो हल देते हैं
बाग़बाँ उनको बनाने पे लगे हैं, कुछ लोग
मुस्कुराती हुई कलियाँ जो मसल देते हैं
वक़्त उनका कोई नुकसान नहीं कर पाता
वक़्त पड़ने पे जो ख़ुद वक़्त बदल देते हैं
सभ्यता गूँजती है आज भी ऐवानों में
हम फ़रिश्ता सिफ़त इन्सान अटल देते हैं
उँगलियाँ काटने वालों को ख़बर कर देना
हाथ दुश्मन के भी हम लोग कमल देते हैं
जो मोहब्बत के पुजारी हैं वो दुनिया भर को
तीर, तलवार, नहीं देते ग़ज़ल देते हैं
आज के दौर का इतिहास भी लिखिए साहेब
आप तो बस हमें गुज़रा हुआ पल देते हैं
'अंजना' अहले मोहब्बत को मोहब्बत वाले
इक मोहब्बत का निशाँ ताजमहल देते हैं

ग़ज़ल

P डॉ. अंजना सिंह सेंगर

बस इसी बात का तो गिला है मुझे
आईना रोज़ टोकता है मुझे

ज़ेहन जितना भी एखतेलाफ़ करे
मशवेरा दिल का मानना है मुझे

सो भी जाऊँ तो ऐ मिरी बेटी
तेरी आँखों में जागना है मुझे

उस से बेदार मुझको रहना है
जो अभी टूटकर मिला है मुझे

हर घड़ी मैं बिखरती रहती हूँ
हर घड़ी वो संभालता है मुझे

उसकी तारीफ़ मुझको करनी है
उसने क्या क्या नहीं कहा है मुझे

सारी दुनिया हसीन कर दूँगी
हज़रत-ए-इश्क़ की दुआ है मुझे

मेरे बारे में कोई राय न दे
तू अभी कितना जानता है मुझे

RNI : UPHIN/26/A0322

पंचायत वॉयस

पंचायत से परिवर्तन...

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

यह पत्रिका देश के ग्रामीण और शहरी जीवन में व्याप्त चुनौतियों के निराकरण एवं बेहतरी की संभावनाओं पर आधारित जन सरोकार से जुड़ी है। हमारा मूलभूत उद्देश्य "पंचायत से परिवर्तन" का है, जहां गांव की पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक की बात होगी। हमारा जोर समाज में पत्रकारिता को मजबूती के साथ खड़ा करने पर है। हमारी कोशिश है कि हिन्दी पत्रकारिता में "तथ्य ही सत्य है" का मूल्य स्थापित हो।

आवश्यकता है:-

पंचायत वॉयस मासिक पत्रिका के लिए ब्यूरो चीफ, नगर संवाददाता एवं विज्ञापन प्रतिनिधि हेतु देश के सभी शहरों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं आप हमारे पते पर संपर्क करें।

दूरभाष: 9876917688

कार्यालय 39/166, नियर यूनिटी सिटी, कल्याणपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226022

panchayatvoice.up@gmail.com www.panchayatvoice.in

Panchayat Voice

आर्थिक सहयोग

जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता के लिए आप हमारा सम्बल बनें, 'पंचायत वॉयस' को करें सहयोग

Account Details
A/c Name : Panchayat Voice
A/c No. : 031402000011565
Bank Name : IDBI Bank
IFSC : IBKL0000314
Branch : Manoj Pandey Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow (UP)-226010

UPI ID : voice26@idbi

Diamond Jewellery
22K, 18K, 14K HM Gold Ornaments
92.5 Pure Silver Ornaments, Utensils & Gift Items
SA
SHANKAR
ABHUSHAN BHANDAR
Malvia Road, Deoria-274001 (U.P.)
Phone: 05568 469847, 9235422574
awnish1963@gmail.com

Mob:
9335032177
Anil Kushawaha
COMPU WORLD
(COMPUTER SALES & SERVICES)
SALES
SERVICES
PRINTERS
COMPUTERS
CCTV
Shop No.– 6, Jalkal Complex, New Colony
Deoria– 274001 (U.P.)
BEST QUALITY PRODUCTS
EXPERT SUPPORT
AFFORDABLE PRICES
TRUSTED SERVICE
email:
compuworld97@gmail.com

पहले भय का परिवेश
आज पर्यटन प्रदेश

अपना यूपी बदल गया

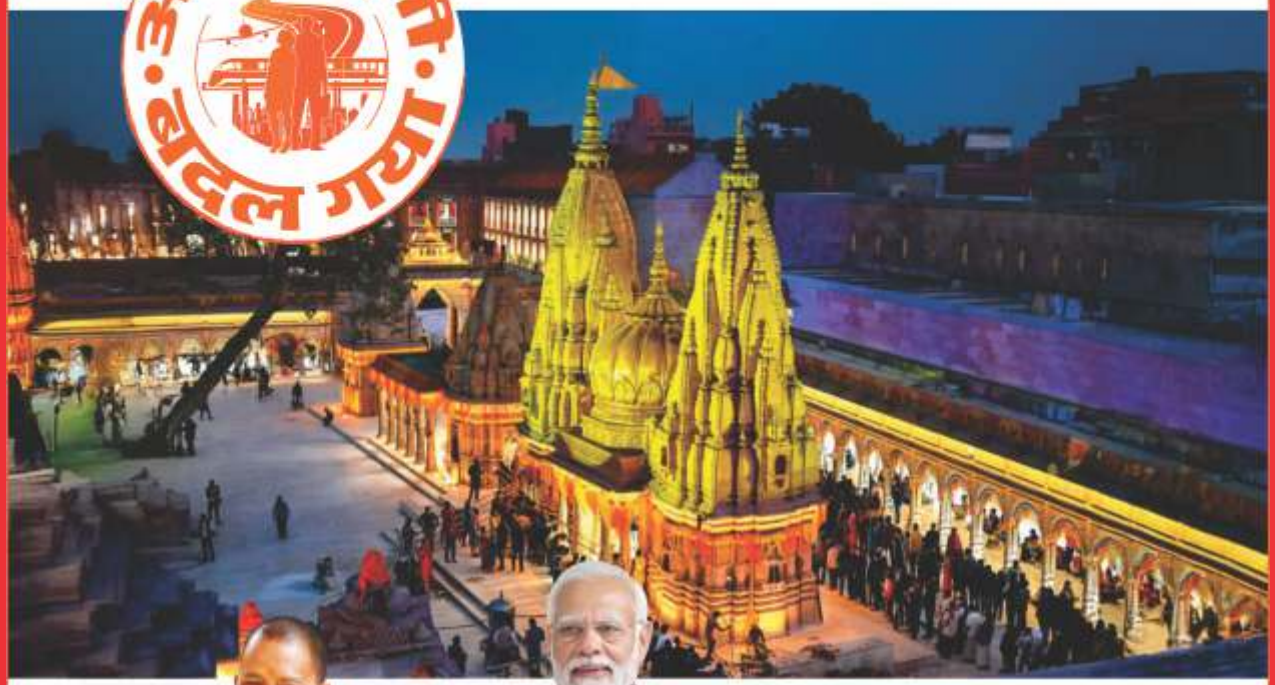

2017 में
23.7 करोड़ पर्यटक

2025 में
156 करोड़+
पर्यटक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP